

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,तृष 22, अंक - 341- मंगलवार 13- अक्टूबर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पहली बार विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च....एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका लगाई,राहुल-अखिलेश समेत 10 पार्टियों के 11 नेता याचिकाकर्ता

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। राहुल,प्रियंका,खड़गे के साथ अन्य विपक्षी सांसद सोमवार शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे। पहले विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च निकाला था। उन्हें 500 मीटर पहले रोक दिया गया था। यह पहली बार है जब विपक्षी नेताओं ने किसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें राहुल गांधी,अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। मार्च के पहले राहुल गांधी ने 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है,इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। रविवार को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया और याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 11 नेताओं के नाम

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में 11 नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे,तृणमूल कांग्रेस के सीगत राय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। इनके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत,माकपा के एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा,झारखंड मुक्ति मोर्चा की महोआ माजी,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई. टी. मोहम्मद बशीर के नाम भी याचिका में हैं।

निर्वाचन आयोग समेत वार प्रतिवादी

याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संभू व विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए 'वोट चोरी' के आरोप लगाए हैं। साथ ही,उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है।



राहुल-खरगे समेत नेताओं ने किए हस्ताक्षर

एसआईआर विवाद को लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव समेत 11 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर रिट याचिका पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि राहुल गांधी की कानूनी टीम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी थी।

राहुल की लीगल टीम ने समय-सीमा बढ़ाने की मांग की...

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के शाम 4:30 बजे बंद होने की समय-सीमा के बाद याचिका दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रही है। आम तौर पर ऐसे मामलों में पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की ई-फाइलिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 24x7 उपलब्ध रहती है।

प्रदर्शन की जगह बदलकर सरकार बच नहीं सकती

अखिलेश यादव ने कहा...आंदोलन और धरना जारी रहेगा। लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी,चुनाव आयोग के साथ मिलकर सविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वह भ्रमशासता में बने रहना चाहती है। वे फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और चुनाव के नतीजे तैयार करते हैं। सरकार प्रदर्शन की जगह बदलकर खुद को नहीं बचा सकती और न ही प्रदर्शन स्थल बदलने से कथित गड़बड़ियां ठिप सकती है। हम लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया कि भाजपा अब भी फर्जी वोट बना रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में दोहरा वोट मौजूद है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता दिखाई दे रहा है।



राहुल गांधी को सिर्फ असुरक्षता फैलाना आता है : अनुराग ठाकुर

भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दलों के मार्च पर निशाना साधा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 'राहुल गांधी जी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन ले ये एक ऐसे नेता हैं जिन्हें न तथ्यों का पता है, न तर्क का पता है और न ही नियम-कानून का पता है। उन्हें सिर्फ असुरक्षता फैलाने, अस्थिरता पैदा करने, संवैधानिक पदों और संस्थाओं को नीचा दिखाने तथा दुनिया भर में भारत की छवि को कमजोर कैसे करना है, उन्हें सिर्फ यही करने आता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण इतना असुरक्षित,अस्थिर और अगंभीर नजर आता है।' अनुराग ठाकुर ने कहा, 'राहुल गांधी,जिनके लंबों पर लब्ज है- वोट चोरी... दरअसल वो कर रहे हैं जनोदेश के साथ सोनाजोरी। राहुल गांधी सिर्फ हवा-हवाई बातें करते हैं, क्योंकि वो हवा-हवाई नेता है। इनके राजनीति का पूरा पैटर्न ही हवा-हवाई है। ये बार बार आरोप लगाते हैं और फिर कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है।



कैंसर रोधी दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-दूसरी दवाओं की कीमत पर रोक क्यों नहीं,27 अक्टूबर तक जवाब मांगा

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब में खुश होने जैसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि जब कैंसर की दवाओं पर मार्जिन तय किया जा सकता है,तो दूसरी दवाओं पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? केंद्र ने बताया कि इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। कोर्ट ने दवाओं की कीमत तय करने के तरीके पर जानकारी देने के लिए सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता को 27 अक्टूबर तक का समय दिया। सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में भारत में कैंसर-रोधी दवाओं की सालाना बिक्री 5,281 करोड़ रही। 2021-22 में यह 3,382 करोड़ थी। यानी तीन साल में बिक्री करीब 56% बढ़ी। केंद्र की ओर से सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिडिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए। बेंच ने कहा, हम मानते हैं



कि परिवहन,कच्चे माल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरी लागत होती हैं। लेकिन ये सभी एमआरपी में शामिल होती हैं। उन्हें असली लागत से 400 गुना ज्यादा कीमत पर बेचने की अनुमति देने का क्या तर्क है? आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? भाटी ने कहा कि भारत में दवाओं की कीमत दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि दवाओं की कीमत एक सीमा से ज्यादा नियंत्रित नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ज्यादा मार्जिन मिलने से दवाएं दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचती हैं। जस्टिस मेहता ने कहा, 'आगर डीपीसीओ से मंजूर दवाएं ग्राहकों तक नहीं

पहुंचतीं, तो मरीजों तक उन्हें पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। असल विवाद यह है कि डीपीसीओ की नियंत्रित सूची में कौन-सी दवाएं होनी चाहिए और कौन-सी नहीं।' केंद्र ने 551 पन्नों के विस्तृत हलफनामे में कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एंसेंशियल मेडिसिन्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तैयार और प्रकाशित करता है। हलफनामे के मुताबिक, नेशनल लिस्ट ऑफ एंसेंशियल मेडिसिन्स को 2011, 2015 और हाल में 2022 में प्रकाशित किया गया था। केंद्र ने कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एंसेंशियल मेडिसिन्स स्टैंडिंग नेशनल कमेटी ऑन मेडिसिन्स तैयार करती है। इसमें सभी संबंधित पक्ष और विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की जगहों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, अब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में तय किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी स्थायी आदेश संख्या एलएंडओ/48/2026 में यह जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के प्रदर्शन और विरोध करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थलों की पहचान के लिए एक समिति बनाई थी। समिति को मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प तलाशने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसकी सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस का यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी स्थायी आदेश संख्या एलएंडओ/48/22 में आंशिक बदलाव करता है। नए आदेश में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने और तीन नए



तीनों जगहों पर प्रदर्शन के लिए नए नियम लागू होंगे?

दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है कि तीनों स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलगत से जारी की जाएगी। यानी प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी बाद में दी जाएगी। फिलहाल आदेश में नए नियमों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए प्रदर्शन से जुड़ी शर्तों, अनुमति लेने की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अलग आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिलेगी।

स्थलों को निर्धारित करने की बात कही गई है। साथ ही, इन स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित एसओपी बाद में जारी करने की जानकारी दी गई है। आदेश पर

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के हस्ताक्षर हैं।

प्रदर्शन करने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? इस बदलाव के बाद दिल्ली

जंतर-मंतर की जगह तीन नए स्थल तय किए गए?

- रामलीला मैदान...इसे प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए नए स्थलों में शामिल किया गया है।
- बुराड़ी मैदान...यहां भी नागरिकों को विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति देने के लिए स्थल निर्धारित किया गया है।
- सीबीडी मैदान, पूर्वी दिल्ली...इसे भी नए प्रदर्शन स्थलों की सूची में जगह दी गई है।

में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए निर्धारित स्थलों की सूची बदल गई है। जंतर-मंतर अब इस आदेश के तहत निर्धारित प्रदर्शन स्थल नहीं रहेगा। इसके बजाय रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को नए स्थल बनाया गया है। हालांकि, इन जगहों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए लागू होने वाली विस्तृत प्रक्रिया और शर्तों का पता संशोधित एसओपी जारी होने के बाद चलेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बदलाव पुराने आदेश में आंशिक संशोधन के रूप में किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 4 आतंकियों की मौत

घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे,बारूदी सुरंग की वजह से उग्र

श्रीनगर, 12 अक्टूबर 2026। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर समेत चार आतंकियों के मारे जाने की खबर है। चारों आतंकियों की पहचान मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फै जान, मोहम्मद वकास और मोहम्मद असीम के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकियों का यह समूह सोमवार दोपहर बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के नंगी टकरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वे बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र में पहुंच गए, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट में चारों आतंकियों की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे सेक्टर में अलर्ट जारी कर दिया है। नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण बल बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा चूक को रोका जा सके। एक अन्य घटना में, भारतीय सेना ने सोमवार को पुंछ के मेंडर सेक्टर के बसोनी इलाके में सीमा पर लगी बाड़ के पास दो पुरानी बारूदी सुरंगों का पता लगाया। अधिकारियों के अनुसार, सुबह 8:25 बजे रास्ता बनाने के काम के दौरान ये सुरंगें मिलीं। सेना के विशेषज्ञों ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए दोनों बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में इसी इलाके में करीब एक दर्जन बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय किया जा चुका है।



नौसेना में शामिल हुआ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट 'मंगरोल'

बंदरगाहों और तटीय रास्तों की सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी, बड़े पलीट ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। कोचिन के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सोएसएल) में निर्मित तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट 'मंगरोल' औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़े का हिस्सा बन गया। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इंडियन नौसेना में कमीशन किया गया यह जहाज भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमताओं को मजबूत करेगा, जहां तटीय पानी में बड़े वॉरशिप को ऑपरेशनल दिकर्ताओं का सामना करना पड़ता है। इसके शामिल होने से नौसेना की पोर्ट, हार्बर और तटीय रास्तों की सुरक्षा करने की क्षमता बढ़ने के साथ ही बड़े पलीट ऑपरेशन में भी मदद मिलेगी। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इस सेरेमनी की अध्यक्षता वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्सल्यन ने की।



इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नौसेना और रक्षा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि और देशी हथियार और सेंसर बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गुजरात के जुनागढ़ जिले के एक तटीय शहर और प्रमुख मछली पकड़ने के बंदरगाह मंगरोल के नाम पर निर्मित यह जहाज पूर्ववर्ती आईएसएस मंगरोल (एम-85) की विरासत को आगे बढ़ाता है। जहाज के नामकरण से नौसेना ने अपने पूर्व

युद्धपोतों की विरासत को संरक्षित करने की परंपरा को जारी रखा है। इस पूर्ववर्ती जहाज ने 07 अप्रैल 2004 तक भारतीय नौसेना की सेवा की थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 80 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना मंगरोल युद्धपोत डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और इंटीग्रेशन हथियारों और सेंसर के इंटीग्रेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है। सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत 80 फीसदी

स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह जहाज डिफेंस शिपबिल्डिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तटीय और उथले पानी में पानी की नीचे के खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया मंगरोल मॉडर्न हथियारों और सेंसर से लैस है,जिसमें अभय हल-माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो, एक स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और मारीच एडवॉर्ड टॉरपीडो डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मुताबिक आईएसएस मंगरोल में एडवॉर्ड सोनार,टॉरपीडो और एसडब्ल्यू रॉकेट लगे हैं,ताकि तटीय पानी में सबमरीन का शिकार किया जा सके। वाटर जेट प्रोपल्शन वाले तीन डीजल इंजन से चलने वाला यह जहाज उथले पानी में ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा मैन्युवैलिटी देता है।

पटाखा बैन...सुप्रीम कोर्ट बोला-कम प्रदूषण वाले तरीके अपनाएं वकील ने कहा...भगवान को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे बीमार हो रहे तो वो भी हैरान होंगे

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-पुनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने लोगों से कम प्रदूषण वाले तरीकों से त्योहार मनाने की अपील की। सुनवाई के दौरान एमिक्स बयूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा, अगर भगवानों को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो वे भी हैरान रह जाएंगे। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।



ऐसा आदेश नहीं देंगे जिसे लागू न किया जा सके : बेंच में जस्टिस जयमाल्या बागची और वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखों से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदेश देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे व्यावहारिक और लागू करने योग्य बनाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस बागची ने पटाखे फोड़ने के धार्मिक आधार पर सवाल उठाया। जागरूकता और कम प्रदूषण वाले पटाखों पर जोर : सीजेआई ने कहा कि लोगों को समझदार बनाना होगा और जागरूक करना होगा। उन्हें बताना होगा कि कौन से पटाखे ज्यादा नुकसानदायक हैं। हमें लोगों को आसानी से लागू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उस समय केवल फुलझड़ियां जलती थीं और दीपक जलाए जाते थे। वरिष्ठ वकील पराजिता सिंह ने कहा कि सही तरीके से लागू किए बिना प्रतिबंध प्रभावी नहीं होंगे।

संपादकीय

सुधारों को तेजी से लागू करके ही भारत बनेगा समृद्ध

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत के सामने एक बड़ा सार्वजनिक सपना है। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने अपना ध्यान काफी हद तक नियंत्रित और सतर्क अर्थव्यवस्था पर रखा, जबकि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने तेजी से औद्योगिकीकरण करके अपनी आय में बड़ा इजाफा किया।

1991 के सुधारों ने भारत की दिशा बदली,पर जमीन की व्यवस्था, अदालती फैसलों और उद्योगों में रोजगार की कमी की वजह से हम दूसरे देशों से पीछे रह गए। अब आने वाले समय में भारत के पास इस अंतर को पाटने का एक शानदार मौका है। बीते कुछ सालों में देश के बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति हुई है। सरकार ने सड़क,रेल, बिजली और इंटरनेट जैसे बुनियादी ढांचे में काफी पैसा लगाया है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट्स और सस्ते इंटरनेट ने आम लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है। ये तमाम बातें निवेशकों को आकर्षित करती हैं और विकास का एक पक्का आधार तैयार करती हैं।

लेकिन सड़क और इंटरनेट होना ही काफी नहीं है,असली काम इनका इस्तेमाल करके बेहतर कारखाने और रोजगार बनाना है। किसी भी कारखाने को लगाने में आने वाली देरी सबसे बड़ी रुकावट है। जमीन की खरीद, पर्यावरण की मंजूरी और बिजली का कनेक्शन मिलने में महीनों लग जाते हैं। अलग-अलग राज्यों में इसका समय अलग होता है। निवेशक किसी राज्य के वादे से ज्यादा वहां की आसान प्रक्रिया को देखते हैं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में अलग-अलग विभाग हैं और सभी जगह से क्लीयरेंस लेने में देरी होती है। नई सड़क या बांध का उद्घाटन करना नेताओं के लिए आसान और दिखने वाला काम है, लेकिन जमीन के विवाद सुलझाना और कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाना ज्यादा वक़्त लेता है। जमीन का मामला सबसे पेचीदा है। गलत या पुराने रिकार्ड होने से जमीन के विवाद बढ़ते हैं, जिससे औद्योगिक विकास रुका रहता है। इसी तरह मजदूर कानून को आसान बनाने की जरूरत है ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को पक्की नौकरी दे सकें।

सिर्फ नई सड़कें और पुल बनाने से बात नहीं बनेगी। हमारे पास पढ़े-लिखे, कुशल और स्वस्थ वर्कर भी होने चाहिए। शिक्षा,स्वास्थ्य और स्क्रिल ट्रेनिंग पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कंजोर्ट के ढांचे पर खर्च करना। हर साल भारत में लगभग एक करोड़ से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में आते हैं। सभी को सरकारी नौकरी या आईटी क्षेत्र में जगह नहीं मिल सकती।इसके लिए मैन्यूफैक्चरिंग,टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और निर्यात पर ध्यान देकर तरक्की की धी।भारत को भी आने वाले दो दशकों में इसी आधार पर काम करना होगा। अगर हम सुधारों को सही ढंग से लागू कर सकें, तो 2047 तक भारत सच में एक विकसित और समृद्ध देश बन सकता है।

लोकतंत्र में विपक्ष और असहमत आवाजों की मौजूदगी



स्वदेश कुमार
 लखनऊ, उत्तर प्रदेश

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका समाज को आईना दिखाने, सत्ता से तीखे सवाल करने और देशहित सर्वोपरि रखने की होती है। लेकिन वर्तमान समय में जनता के बीच यह गंभीर चिंता और विमर्श का विषय बन चुका है कि क्या आज का मीडिया अपनी इस मूल जिम्मेदारी को समझ पा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन नेताओं या शक्तिस्थलों को जनता ने चुनवांयों में ठुकरा दिया है या जो जनभावनाओं पर खरे नहीं उतरे, उन्हें भी समाचार माध्यमों पर लगातार बड़ी सुर्खियां और विशेष कवरेज दी जाती है। इस विमर्श के केंद्र में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मीडिया जनबुझकर देशहित की अनदेखी कर किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट कर रहा है या फिर इसके पीछे कुछ गहरे व्यावसायिक और राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं।इस पूरी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले



घरानों का स्वामित्व सीधे या परोक्ष रूप से उन कोंपैरिट समूहों या प्रभावशाली लोगों के हाथों में है, जिनके अपने विशिष्ट व्यावसायिक या राजनीतिक हित होते हैं। जब मीडिया का बाँचा कुछ चुनिंदा हथों में सिमट जाता है, तो निष्पक्षता की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी खास राजनेता या दल को बढ़ावा देना, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में और चाहे जनता ने उसे कितना भी नकारा हो, उस मीडिया घयने के दीर्घकालिक हितों का हिस्सा हो सकता है। यह स्थिति सीधे तौर पर देशहित को समझौता करती है,क्योंकि जनता को वह सच नहीं दिखाया जाता, जो उनके लिए जरूरी है,बल्कि वह नैरेटिव परोसा जाता है,जो किसी व्यक्ति या संगठन के अनुकूल हो।इस प्रवृत्ति को क्या देश के साथ बड़ी बेईमानी कहा

जा सकता है,इसे विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखना होगा। जब मीडिया प्रशासन और जनता के बीच एक ईमानदार पुल का काम करने के बजाय किसी व्यक्ति विशेष की पीआर (पब्लिक रिलेशंस) एजेंसी की तरह व्यवहार करने लगता है, तो यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। जनता समाचारों को सत्य मानकर अपने लोकतांत्रिक निर्णय लेती है। यदि उसे बार-बार केवल एक ही पक्ष या किसी खास अग्रासंगिक चेहरे की ही सबसे बड़े मसीह या मुख्य बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा, तो जनमानस की सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित होती है। यह देशहित के साथ इसलिए बेईमानी है, क्योंकि यह वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका कर देश के विकास की गति को धीमा करता है। हालाँकि,इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। लोकतंत्र में विपक्ष और असहमत आवाजों की मौजूदगी अनिवार्य है। कई बार मीडिया उन नेताओं को भी मंच देता है, जो चुनाव हार चुके होते हैं या जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा नापसंद किए जाते हैं, ताकि सत्ता पक्ष की

नीतियों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण सामने आ सके। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और जनसरोकार के मुद्दों को पूरी तरह दरकिनार करके केवल राजनीतिक नृराकुशरी और व्यक्ति-केंद्रित बहसों को ही चौबीसों घंटे प्रसारित किया जाता है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से विमुख हो रहा है।लब्बालुआब यह है कि ऐसी स्थिति केवल मीडिया की ही नहीं, बल्कि दर्शकों के रूप में समाज की भी परीक्षा लेती है। जब तक दर्शक सनसनीखेज खबरों और व्यक्ति-विशेष के प्रचार को देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक व्यावसायिक कारणों से मीडिया अपनी इस कार्यशैली को नहीं बदलेगा। आज की पत्रकारिता में विश्वसनीयता और तटस्थता की जो कमी दिख रही है, उसे दूर करने के लिए मीडिया घरानों को आत्ममंथन करने और देशहित को अपने व्यावसायिक लाभ से ऊपर रखने की सख्त आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ अपनी पवित्रता और जनता का विश्वास बनाए रख सके।

मुखौटे : झूठी अच्छाई,सच्ची बुराई



हेमेन्द्र श्रीरसागर,बालाघाट,मध्यप्रदेश
 चेहरे तो सबके पास बहुत हैं, बस एक रावण ही था जिसने छिपाए नहीं। रामायण का रावण युगों-युगों से अधर्म, अहंकार और बुवाई के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। विजयादशमी की हर शाम जलते हुए रावण के पुतले के साथ समाज यह संदेश देता है कि अंततः सत्य की विजय होती है और असत्य का विनाश। लेकिन जब हम रावण के दस सिरों के प्रतीकात्मक अर्थ और उस पर कही गई इस पंक्तियों। चेहरे तो सबके पास बहुत हैं,बस एक रावण ही था जिसने छिपाए नहीं। पर विचार करते हैं, तो यह आधुनिक सभ्यता के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ती है। बेला में इस नवरात्र के दशहरा पर हम दशानन का दहन कर सच्चाई का विजय पर्व मनाने की इतिश्री करेंगे।

यह विचार रावण के दुष्कर्मों का महिमामंडन नहीं करता,बल्कि आज के समाज में व्याप्त पाखंड और छद्म आचरण की गहरी शल्य-चिकित्सा करता है। रावण के पास दस सिर थे, यानी दस अलग-अलग मनोवृत्तियां और विचार। लेकिन उसकी खासियत यह थी कि उसने कभी अपने किसी रूप को छिपाने की कोशिश नहीं की। वह जैसा भी था,अहंकार,विद्वान्, महाज्ञानी या कसूर खुलेआम था। उसने अच्छाई के दशहरा पर हम दशानन का दहन कर सच्चाई का विजय पर्व मनाने की इतिश्री करेंगे।

यह विचार रावण के दुष्कर्मों का महिमामंडन नहीं करता,बल्कि आज के समाज में व्याप्त पाखंड और छद्म आचरण की गहरी शल्य-चिकित्सा करता है। रावण के पास दस सिर थे, यानी दस अलग-अलग मनोवृत्तियां और विचार। लेकिन उसकी खासियत यह थी कि उसने कभी अपने किसी रूप को छिपाने की कोशिश नहीं की। वह जैसा भी था,अहंकार,विद्वान्, महाज्ञानी या कसूर खुलेआम था। उसने अच्छाई का फर्जी आवरण पहनकर समाज को धोखा देने का प्रयास नहीं किया। उसका

अधर्म भी सामने था और उसकी शत्रुता भी खुली थी।

इसके ठीक विपरीत,आज के आधुनिक ईसान को देखिए। आज व्यक्ति चेहरे पर चेहरा लगाए घूम रहा है। बाहर से बेहद सौम्य,आसमीय और सदाचारी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से ईर्ष्या,स्वाधं और छल-कपट से भरा हो सकता है। आज का समाज बहु-चेहरा संस्कृति का शिकार है। हम सामने मित्र हैं और पीठ पीछे शत्रु, सार्वजनिक मंचों पर नैतिकता के उपदेशक हैं और व्यक्तिगत जीवन में स्वार्थी। आज के युग में सबसे बड़ा खतरा उस बुवाई से नहीं है जो खुलकर सामने आती है, क्योंकि खुली बुवाई से सावधान रहना तमाचा जड़ती है। बेला में इस नवरात्र के दशहरा पर हम दशानन का दहन कर सच्चाई का विजय पर्व मनाने की इतिश्री करेंगे।

यह उर्क वास्तव में हमें अपने भीतर झांके और आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। यह सवाल उठाती है कि दस सिरों वाले रावण की स्रष्टा बेहतर थी या एक सिर वाले आधुनिक मानव के वे दर्जनों छिपे हुए मुखौटे? यदि हम एक बेहतर और पारदर्शी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें दोहरे चरित्र की इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। झूठी अच्छाई के सौ मुखौटे पहनने से कहीं अधिक सम्मानजनक है कि ईसान अपने वास्तविक रूप में निष्कल और पारदर्शी बनकर सच्ची बुवाई करें।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

आन्दोलन वही,जो सार्थक मुद्दा,दिशा एवं भरोसे से जुड़ा हो



ललित गर्ग,पटपड़गंज,नई दिल्ली

लोकतंत्र में असहमति उसकी कमजोरी नहीं,बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। सरकार से सवाल पूछना, नीतियों का विरोध करना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना नागरिक स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा केवल इस बात से नहीं होती कि विरोध करने की कितनी स्वतंत्रता है, बल्कि इससे भी होती है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग किस उद्देश्य,किस भाषा और किस पद्धति से किया जा रहा है। किसी आंदोलन का मुद्दा कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो,यदि उसका नेतृत्व दिशाहीन हो जाए,भाषा उतेजक बन जाए और पद्धति हिंसा अथवा अराजकता की ओर बढ़ने लगे, तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए आज देश के सामने प्रश्न केवल आंदोलनों का नहीं, बल्कि उनके चरित्र,विश्वासनीयता और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी है। दिल्ली में हाल के विरोध प्रदर्शनों और उन पर प्रशासन की सख्ती के बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने एक बार फिर लोकतंत्र की सीमाओं और संभावनाओं पर बहस छेड़ दी है। एक ओर शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का अधिकार है,तो दूसरी ओर सार्वजनिक व्यवस्था,नागरिक सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना शासन का दायित्व है। इन दोनों के बीच संतुलन ही संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। न तो सरकार को कानून-व्यवस्था के नाम पर नागरिक स्वतंत्रताओं के अनावश्यक दमन

की छूट दी जा सकती है और न ही आंदोलनकारियों को लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में सार्वजनिक जीवन को बाधित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है। संविधान अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी जोड़ता है। आज सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जनांदोलनों की दिशा कौन तय कर रहा है?क्या आंदोलन वास्तव में जन समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हो रहे हैं, अथवा जनता के असंतोष को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का साधन बनाया जा रहा है? यह प्रश्न किसी एक दल या संगठन तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष,सामाजिक संगठन हों या जनसमूह,सभी को अपने आचरण की कसौटी संविधान,नैतिकता और जनहित को बनाना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, कमियों को सामने लाता है और जनहित के मुद्दों के राजनीतिक विमर्श में स्थान देता है। लेकिन विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करना भी है। यदि हर असहमति को सत्ता के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष में बदलने का प्रयास किया जाए, हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक षड्यंत्र बताया जाए और प्रत्येक जनसमस्या को व्यापक अव्यवस्था का प्रतीक बना दिया जाए, तो वास्तविक मुद्दे शोर में खोने लगते हैं। इसी तरह सरकार भी यदि आलोचना को शत्रुता समझने लगे, तो लोकतांत्रिक संवाद की संभावनाएं संकुचित हो जाती हैं।

आंदोलन की साख उसके मूल उद्देश्य एवं भरोसे से बनती है। जिस मुद्दे को लेकर लोग एकत्र होते हैं, उसकी स्पष्टता, तथ्यात्मक प्रामाणिकता और समाधान की दिशा आंदोलन की विश्वसनीयता निर्धारित करती है। जब मूल प्रश्न पीछे छूट जाता है और राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अथवा वैचारिक टकराव केंद्र में आ जाते हैं, तब आंदोलन



की ऊर्जा बिखरने लगती है। जनसमर्थन जुटाना और जनविश्वास अर्जित करना दो अलग-अलग बातें हैं। भीड़ किसी क्षणिक आक्रोश का परिणाम हो सकती है,लेकिन जनविश्वास निरंतर नैतिक आचरण और रचनात्मक कार्यों से अर्जित होता है। भारत का लोकतांत्रिक इतिहास इस संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 1974 का छत्र आंदोलन और लोकनायक जय प्रकाश नारायण का नेतृत्व बताया है कि जनआक्रोश को रचनात्मक परिवर्तन की शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई और शासन संबंधी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जयप्रकाश नारायण ने इस असंतोष को व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की दिशा देने का प्रयास किया।

आज के आंदोलनों को इस ऐतिहासिक अनुभव से सीखना चाहिए। किसी भी आंदोलन की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितनी सड़कें बंद हुईं, कितने लोग एकत्र हुए या कितने दिनों तक विरोध चला। उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि उसने किस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जनजीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाया और समाज में संवैधानिक चेतना को कितना मजबूत किया। वर्तमान समय में इंटरनेट मीडिया ने जनमत निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब कोई घटना कुछ ही मिनटों में व्यापक बहस का विषय बन सकती है। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है,क्योंकि इससे आम नागरिकों

को अपनी बात रखने और प्रशासन से जवाब मांगने का मंच मिला है। लेकिन यही माध्यम भ्रामक सूचनाओं, अधूरे तथ्यों, भावनात्मक अभियानों और अफष्ट आरोपों को भी तेजी से प्रसारित कर सकता है। हैशटैग, वायरल वीडियो

और ऑनलाइन समर्थन अपने आप में किसी आंदोलन की नैतिक प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। किसी आरोप की गंभीरता का निर्धारण उसके प्रमाणों से होना चाहिए, उसकी लोकप्रियता से नहीं। यदि आंदोलनकारी तथ्यों की पुष्टि किए बिना आरोप लगाते हैं,तो वे अपने ही उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार प्रशासन का दायित्व है कि वह आलोचनात्मक आवाजों को केवल इसलिए संदिग्ध न माने कि वे सरकार के विरुद्ध हैं। पारदर्शिता,तथ्यपरक संवाद और निष्पक्ष जांच ही अविश्वास को दूर करने के प्रभावी उपाय हैं। आज युवाओं के पास डिजिटल तकनीक,नवाचार,उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता के अनेक अवसर हैं। उनकी ऊर्जा केवल विरोध तक सीमित न रहे,बल्कि समाधान निर्माण में भी लगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो तो पारदर्शिता के व्यावहारिक उपाय सामने आए,युवावी सुधारों की मांग हो तो प्रमाण आधारित सुझाव प्रस्तुत किए जाएं, प्रशासनिक अन्याय का प्रश्न हो तो कानूनी और संस्थागत रस्तों को मजबूत किया जाए। विरोध की सार्थकता तब बढ़ती है,जब वह किसी बेहतर व्यवस्था की कल्पना और निर्माण का आधार बनता है।

जनांदोलनों के संदर्भ में विदेशी शक्तियों की चेतना पर भी चर्चा होती रही है। यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राष्ट्रीय हितों,बाहरी प्रभावों और सूचना के प्रवाह को लेकर सतर्कता बरती जाए। लेकिन इस विषय पर भी भावनाओं अथवा आशंकाओं के बजाय प्रमाणों के आधार पर बात होनी चाहिए। किसी

कम अंक जीवन की असफलता नहीं, बल्कि अपनी रणनीति सुधारने का अवसर

1500 बच्चों को सिखाए तनाव से निपटने के गुर



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

परीक्षा में कम अंक आने या किसी परेशानी के कारण निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अंक किसी बच्चे की पूरी प्रतिभा और व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। यह संदेश 'जीवन अमोल है' अभियान के तहत सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल और सेंट जेवियर बीएड कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में दिया गया। समाज सेविका एवं अधिवक्ता शिल्पा पाण्डेय के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1500 बच्चों को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक (विशेष मामले) अमोलक सिंह हिल्लों ने कहा कि परिवार के संस्कारों, सनातन विरासत और सामाजिक मर्यादाओं से जुड़े रहने से बच्चों का व्यक्तित्व मजबूत बनता है। वहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्रह्माकुमारी संस्थान की संचालिका बीके विद्या दीदी ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के तरीके बताए। उन्होंने बच्चों को नशामुक्ति का संकल्प भी दिलाया। मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की काउंसलर अंजुला मिश्रा ने बच्चों को संतुलित खानपान और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. पैकरा ने बच्चों को बिना दबाव के जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी जीवन से बड़ी नहीं है। बच्चों को

अपनी मानसिक स्थिति के प्रति सजग रहना चाहिए और परेशानी होने पर मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।
कम अंक असफल जीवन का प्रमाण नहीं : अभियान की संयोजक शिल्पा पाण्डेय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन करते रहना चाहिए। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा कि कम या ज्यादा अंक मेहनत दिलाया। मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक की काउंसलर अंजुला मिश्रा ने बच्चों को संतुलित खानपान और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. पैकरा ने बच्चों को बिना दबाव के जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी जीवन से बड़ी नहीं है। बच्चों को

असफलता नहीं, बल्कि अपनी रणनीति सुधारने का अवसर है।

मोबाइल के सदुपयोग और अनुशासन पर जोर...

कार्यक्रम में सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य माइकल तिकी ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने संवेदनशील विषय पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए आयोजकों की सराहना की और बच्चों के उच्चल भविष्य की कामना की। विजन की स्वयंसेवक ऐश्वर्य सिद्धि ने मोबाइल के दुरुपयोग के प्रति सचेत करते हुए उसके सीमित और सार्थक उपयोग की अपील की। संगीता ने बच्चों को नियमित अनुशासन अपनाने, जबकि राजू यादव ने बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान हर्षल यादव ने व्यवस्था और अनुशासन की जिम्मेदारी संभाली।

जेएनयू मामले को लेकर महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव

छात्राओं से कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को अम्बिकापुर में विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर सभा करने के बाद कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़ ने किया। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने छात्राओं से जुड़े आरोपों की गंभीर बताते हुए जांच के जरिए सच्चाई सामने लाने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री फूलेश्वरी

सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। वहीं, जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़ ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर महिला मोर्चा आवाज उठाता रहेगा।

पदाधिकारियों ने भी किया संबोधित : सभा को जिला महामंत्री विनोद हर्ष, अरुणा सिंह, मधु चौदाह, प्रिया सिंह, माया मिश्रा, शकुंतला पांडेय, रजनी बिंद, किरण सोनी, प्रियंका चौबे, सरस्वती यादव, शालिनी सिंह और रूपा गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया।

प्रदर्शन में मधुसूदन शुक्ला, जनमेजय मिश्रा, मनोज गुप्ता, रूपेश दुबे, मनोज कसारी, नीलम राजवाड़े, सावित्री जायसवाल, बुधमते कुजूर, नेहा सोनवानी, अर्चना सिंह, मयंक जायसवाल, संजीव वर्मा, रीना भारती, मीरा सिंह, अर्चना वर्मा, रीना रॉय, राखी यादव, सरोज सिंह, नीलम रॉय, निमत दास, सीमा कश्यप, आशा शुक्ला, ज्ञातीन परमार, निरंजन रॉय, मनोज सोनी, आयुष दुबे, सुधांशु चौबे, सविता शर्मा, शिरीष भगत, प्रभा, राधा, फूल कुमारी, रवि विश्वकर्मा, उज्ज्वल शर्मा और नवराज यादव सहित भाजपा एवं महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अवैध खनिज परिवहन पर खनिज अमले की कार्रवाई, चार टीपर वाहन जब्त बिना अग्निवहन पास खनिज परिवहन करते पकड़े गए वाहन



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर सरगुजा के निर्देशन में खनिज अमले द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 11 अक्टूबर 2026 को अम्बिकापुर एवं धौरपुर क्षेत्र में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन के चार मामले सामने आए, जिनमें चार टीपर वाहनों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान वाहन क्रमांक CG 29 AH 8038 के मालिक शैलेश कुमार तथा CG 29 AG 1247 के मालिक मनोज कुशवाहा के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों वाहनों को कलेक्टर कार्यालय परिसर, अम्बिकापुर में रखा गया है। इसी प्रकार वाहन क्रमांक CG 15 EJ 4223 के मालिक अतुल जायसवाल तथा CG 15 EE 9671 के मालिक इन्देव गुप्ता के वाहनों पर भी बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन

करने के मामले में प्रकरण दर्ज कर उन्हें जब्त किया गया है। इन दोनों वाहनों को अग्रिम आदेश तक थाना धौरपुर की अभिरक्षा में रखा गया है।

नए नियमों के तहत होगी कार्रवाई : खनिज परिवहन के इन मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के 22 जून 2026 को संशोधित नियम 71 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संशोधित नियम 71(3) के अनुसार अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये का शमन शुल्क अथवा 2,000 रुपये प्रति टन की दर से निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो, वसूल किए जाने का प्राधान्य है। इसके अतिरिक्त संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जांच और कार्रवाई खनिज अमला द्वारा लगातार जारी रहेगी।

शासकीय मद की भूमि को त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर निजी मद में दर्ज करने पर हल्का पटवारी निलंबित

मूल अभिलेखों का मिलान किए बिना शासकीय मद की भूमि को निजी मद में दर्ज करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर सरगुजा ने राजस्व प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर शासकीय भूमि को निजी मद में दर्ज करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में धोरा लापरवाही बरतने पर हल्का पटवारी श्री सुरेश कुमार डाहिरें को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री डाहिरें पूर्व में ग्राम लालमाटी, तहसील लुण्डा-धौरपुर में हल्का पटवारी के पद पर पदस्थ थे तथा वर्तमान में तहसील लखनपुर में पदस्थ हैं। नायब तहसीलदार, उप तहसील खुनाथपुर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर के राजस्व प्रकरण में भूमि खसरा नंबर 7082 के संबंध में तत्कालीन पटवारी द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया था। जांच में पाया गया कि पटवारी ने स्थल पर वास्तविक कब्जेदार की जानकारी प्राप्त किए बिना त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार कर शासकीय मद की भूमि को निजी मद में मूल अभिलेखों का मिलान किए बिना निजी व्यक्ति के नाम में दर्ज करने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस संबंध में पटवारी श्री डाहिरें को 11 सितंबर 2026 को कारण बताओ सूचना प्रारंभ किया गया था। उनके द्वारा 15 सितंबर 2026 को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री डाहिरें का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार, लखनपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भता देय होगा।

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

विजयादशमी महोत्सव 2026 में इस बार रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ सरगुजा की लोकसंस्कृति के रंग भी बिखरेगे। सरगुजा सेवा समिति, नागरिक समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले महोत्सव के तहत 13 और 14 अक्टूबर को संभागा स्तरीय रामचरितमानस गायन प्रतियोगिता तथा 16 अक्टूबर को पारंपरिक शैला और सुगा लोक नृत्य प्रतियोगिता होगी। खास बात यह है कि इस वर्ष पुरुष और महिला मानस मंडलियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सभी प्रमुख प्रतियोगिताएं कलाकेंद्र मैदान के खुले प्रांगण में होंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद ले सकें।

13-14 अक्टूबर को मानस गायन और राम रूप सज्जा : महोत्सव के तहत 13 एवं 14 अक्टूबर परंपराओं और लोककला को स्तरीय रामचरितमानस गायन एवं राम रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें सरगुजा संभागा की मानस मंडलियों अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इस बार पारंपरिक पुरुष मानस मंडलियों के साथ महिला मानस मंडलियों के लिए भी स्वतंत्र प्रतियोगिता रखी गई है। दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मंडलियों को अलग-अलग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन मानस के जानकारों का निर्णायक मंडल करेगा। महिला मानस मंडलियों को अलग मंच देने की पहल धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में महिलाओं की

ब्रह्माकुमारी केंद्र में चैतन्य देवियों की झांकी शुरू, 20 अक्टूबर तक कर सकेंगे दर्शन दीप प्रज्वलन और आरती के साथ शुभारंभ, विद्या दीदी ने कहा...

आध्यात्मिक ज्ञान से विकारों का नाश कर जीवन को बनाए स्वर्ग समान



—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर में चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम में आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मक सोच और देवी स्वरूप के श्रेष्ठ गुणों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। झांकी के दर्शन के लिए शहरवासियों को 20 अक्टूबर तक अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरगुजा विशेष शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह हिल्लों, विशिष्ट अतिथि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी राकेश बघेल तथा उप निरीक्षक अभय तिवारी उपस्थित रहे।

इनके अलावा वरिष्ठ समाजसेविका वंदना दाता, समाजसेवी अजय तिवारी (आर्ट ऑफ लिविंग), नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के संयोजक मंगल पाण्डेय, अमृत लाल प्रधान, शिल्पा पाण्डेय, हिना खान, संतोष कुमार विश्वकर्मा, निशा बहन तथा ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका विद्या दीदी सहित अन्य अतिथियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर विद्या दीदी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के भीतर मौजूद आसुरी संस्कारों और विकारों को समाप्त करने का मार्ग दिखाता है। देवी-देवताओं के गुणों को केवल पूजा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें अपने व्यवहार और जीवन में उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब



व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाता है, तो परिवार में सुख-शांति और समाज में सद्भाव का वातावरण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ बनाकर स्वर्ग समान बनाया जा सकता है। मुख्य अतिथि अमोलक सिंह हिल्लों ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ऐसे आयोजन लोगों को शांति, सद्भाव और सकारात्मक जीवनशैली की ओर प्रेरित करते हैं। समाजसेविका शिल्पा पाण्डेय ने चैतन्य देवियों की झांकी को शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराने वाला आयोजन बताया। वरिष्ठ समाजसेविका वंदना दाता ने देवी स्वरूप के गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता

पर जोर दिया। वहीं, समाजसेवी मंगल पाण्डेय ने कहा कि अध्यात्म से जुड़कर व्यक्ति का सर्वोच्च विकास संभव है। इसके लिए अपने अविशुद्धों को दूर कर श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाना जरूरी है। कार्यक्रम में देवी भजनों की प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया। उपस्थित अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।

20 अक्टूबर तक शाम 6:30 से रात 10 बजे तक दर्शन : ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी 20 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक शहरवासियों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। श्रद्धालु निर्धारित समय में पहुंचकर झांकी के दर्शन कर सकेंगे।

देवी भक्ति गीत 'महामाया माई-अंबिका के दुवारी' से निधि श्री विश्वकर्मा ने बिखेरी सुरों की भक्ति, सरगुजा का बढ़ाया मान

वाक्यिक निधि श्री की प्रवाज में तब मां महामाया का भक्ति गीत, रंगीत रंगोवन से लेकर वीडियो निर्माण तक कलाकेंद्र की टीम ने निगई प्रथम भूमिका

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

मां महामाया के प्रति आस्था और भक्ति को सुरों में पिरोकर गायिका निधि श्री विश्वकर्मा ने अपने गीत 'महामाया माई-अंबिका के दुवारी' के माध्यम से सरगुजा का नाम रोशन किया है। देवी भक्ति पर आधारित इस गीत में उनकी गायकी के साथ संगीत की मधुरता और भक्ति भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। गीत को लेकर क्षेत्र में चर्चा हो रही है और मां महामाया के भक्तों के बीच इसकी सराहना की जा रही है। निधि श्री विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा की पुत्री हैं। उन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से देवी भक्ति गीत को स्वर देकर धार्मिक आस्था को संगीत के जरिए प्रस्तुत किया है। 'महामाया माई-अंबिका के दुवारी' शीर्षक ही मां महामाया के प्रति श्रद्धा और छत्तीसगढ़ की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ाव का भाव व्यक्त करता है। गीत के जरिए श्रोताओं तक भक्ति और श्रद्धा का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस गीत को Shamikashiproductions ने प्रस्तुत किया है। गीत की गायिका निधि श्री हैं, जबकि संगीत सौरभ

वैभव और प्रिंस सुरशीला पटेल ने तैयार किया है। गीत के बोल भी प्रिंस सुरशीला पटेल ने लिखे हैं। संगीत संयोजन की जिम्मेदारी सौरभ लोखंडे ने निभाई है। मिक्सिंग और मास्टरिंग विसेंट जोसेफ ने की है, जिससे गीत को अंतिम संगीत स्वरूप दिया गया। गीत के वीडियो निर्माण में भी टीम के सदस्यों ने अपनी भूमिका निभाई है। वीडियो और यूट्यूब प्रबंधन का काम जयंथ कौंडिया ने संभाला, जबकि वीडियो निर्माण का श्रेय रायपुर के STUDIO7 और



कल्पेश टांक को दिया गया है। देवी भक्ति गीतों की विशेषता यह होती है कि वे केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं से भी जुड़े हैं। ऐसे गीत धार्मिक अवसरों, पूजा-अर्चना और नवरात्र जैसे पर्व पर भक्तिमय वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'महामाया माई-अंबिका के दुवारी' भी इसी भक्ति परंपरा से जुड़ा गीत है।

मरीजों को मिलेगी ‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस की सौगात, लेकिन रेडक्रॉस के आमंत्रण पत्र में नामों के क्रम पर सवाल!

मरीजों को एंबुलेंस की सौगात,रेडक्रॉस के आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल पर सवाल!

‘डॉक्टर आपके द्वार’ का शुभारंभ,लेकिन रेडक्रॉस में नामों के क्रम पर उठे सवाल!

चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन का नाम सबसे नीचे क्यों? रेडक्रॉस के आमंत्रण पत्र पर चर्चा

सेवा में सब बराबर,लेकिन आमंत्रण पत्र में पदों का क्रम किस आधार पर? रेडक्रॉस से सवाल

13 अक्टूबर को ‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस का शुभारंभ,उससे पहले रेडक्रॉस के आमंत्रण पत्र ने खड़े किए सवाल

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने के उद्देश्य से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी,जिला शाखा सूरजपुर की ओर से 13 अक्टूबर को ‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस का शुभारंभ किया जाएगा। जिला चिकित्सालय सूरजपुर में मंगलवार सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में छतीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्तदान शिविर, पौधरोपण,सेवा संस्थाओं का सम्मान,अंगव्री एवं रक्तवीर सम्मान और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपकरण वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। रेडक्रॉस सोसायटी की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं और मानवीय सहायता को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुविधायुक्त एंबुलेंस के माध्यम से मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने की मंशा है,वहीं,रक्तदान और पौधरोपण जैसे कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा,लेकिन जनसेवा की लक्ष्य पहल के बीच आयोजन के आमंत्रण पत्र में पदाधिकारियों के नामों के क्रम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है,सवाल उठ रहा है कि जब कार्यक्रम रेडक्रॉस सोसायटी का है, तो संस्था के पदाधिकारियों की सूची तैयार करते समय पदों की गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल का कितना ध्यान रखा गया? एक ओर मरीजों को सुविधा देने वाली एंबुलेंस के शुभारंभ की तैयारी है, तो दूसरी ओर आमंत्रण पत्र में नामों की व्यवस्था को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं, ऐसे में आयोजन की सकारात्मक पहल के साथ इस औपचारिक पक्ष पर भी स्पष्टता जरूरी हो गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल होंगे मुख्य अतिथि-कार्यक्रम में छतीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-विकास विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, आमंत्रण के अनुसार,विशिष्ट अतिथियों में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े,वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकड़ा, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भूलन सिंह मरावी और विधायक शकुंतला सिंह पोते शामिल हैं।

प्रसव पीड़ा के बाद मेडिकल कॉलेज में जच्चा-बच्चा की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। प्रसव पीड़ा के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर लाई गई 34 वर्षीय गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। महिला को बलरामपुर जिले के रेवपुर ग्रामस्थित स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से रेफर किया गया था। अस्पताल पहुंचने पर जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के धंधापुर इमराबारा निवासी भुवनेश्वरी (34) नौ माह की गर्भवती थी। 11 अक्टूबर की शाम उस प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इसके बाद परिजन उसे रेवतपुर पीएचसी लेकर पहुंचे। वहां महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर रेफर कर दिया। परिजन महिला को लेकर 12 अक्टूबर की सुबह करीब 3.40 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी। महिला की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पत्र परियोजना को सौंप दिया गया। फिलहाल परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप नहीं लगाया है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई,इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

खदान खुलवाने और पैसा नहीं देने का आरोप लगाकर मारपीट

सीएमडीसी कंठाधर के पास की घटना,दो जान ते गाले की धमकी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरिमा जुनापारा निवासी एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों को विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। कमलेश्वरपुर निवासी पिपा राम पिता मनोराम (35) ने पुलिस को बताया है कि 6 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 4 बजे वह बरिमा माईस सीएमडीसी कांठाधर के पास था,तभी गांव के माझा,जयलाल और कुदारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि खदान तुम्हीं खोले हो और हम लोगों को जमीन के बदले पैसा नहीं दे रहे हो। इसके बाद वे गालीगलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर तीनों ने हाथ-मुक्का,लात और चप्पल से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर माझा,जयलाल, कुदारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणि पैकड़ा,जिला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े,नगर पालिका परिषद सूरजपुर की अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े तथा रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल,वाइस चेयरमैन ओंकार पाण्डेय,राज्य प्रतिनिधि अशोक अग्रवाल और कोषाध्यक्ष श्रवण जैन सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति प्रस्तावित है,रेडक्रॉस सोसायटी की प्रबंध समिति के सदस्यों,आजीवन सदस्यों और गणमान्य नागरिकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदना से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस से जरूरतमंदों को राहत की उम्मीद-स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,जरूरतमंद मरीजों को समय पर सहायता मिलना भी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसी दृष्टि से रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से ‘डॉक्टर आपके द्वार’एंबुलेंस का शुभारंभ महत्वपूर्ण पहल है, विशेषकर उन मरीजों के लिए एंबुलेंस सेवा उपयोगी हो सकती है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचने में कठिनाई होती है या जिन्हें समय पर परिवहन सहायता की जरूरत पड़ती है,हालांकि, इस सेवा का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता कि एंबुलेंस का संचालन किस व्यवस्था के तहत किया जाएगा, जरूरतमंद इसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे और सेवा की उपलब्धता किन क्षेत्रों तक सुनिश्चित होगी,एंबुलेंस को सुविधायुक्त बताया गया है,लेकिन उपलब्ध जानकारी में इसके सभी उपकरणों और संचालन की विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, ऐसे में सेवा शुरू होने के साथ संपर्क नंबर,उपलब्ध सुविधाओं और संचालन संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो आम नागरिकों को इसका लाभ लेने में आसानी होगी,किसी भी जनहितकारी योजना की सफलता केवल शुभारंभ तक सीमित नहीं होती,असली सफलता तब मानी जाएगी,जब जरूरत के समय मरीजों को सेवा मिले और एंबुलेंस का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे, जिनके लिए इसकी व्यवस्था की गई है।

रक्तदान, पौधरोपण और दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण-शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, इसका उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता में सहायता करना है, इसके साथ ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा,सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करने की भी योजना है, अंगदान और रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों से जुड़े लोगों को अंगवीर एवं रक्तवीर सम्मान दिया जाएगा,वहीं,जरूरतमंद दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे,जिससे उन्हें दैनिक जीवन में सहायता मिलने की उम्मीद है, इन सभी गतिविधियों का महत्व तभी बढ़ेगा,जब कार्यक्रम के बाद भी इनके उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए पौधरोपण के बाद पौधों की देखभाल,रक्तदान के प्रति निरंतर जागरूकता और दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराना ऐसे प्रयासों को अधिक सार्थक बना सकता है।



सूरजपुर में 13 अक्टूबर को ‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस का होगा शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हाथों शुभारंभ, रक्तदान शिविर, पौधरोपण, सेवा संस्थाओं का सम्मान और निःशुल्क उपकरण वितरण का आयोजन

रेडक्रॉस के आमंत्रण पत्र में नामों के क्रम पर सवाल!

चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन का नाम सबसे नीचे क्यों ?

जनसेवा के आयोजन के बीच नामों के क्रम पर क्यों उठे सवाल ?

कार्यक्रम की तैयारियों के बीच आमंत्रण पत्र में पदाधिकारियों के नामों का क्रम भी चर्चा का विषय बना हुआ है,विशेष रूप से चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल के बाद वाइस चेयरमैन ओंकार पाण्डेय का नाम किस क्रम में और किस आधार पर रखा गया,इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं,सवाल यह है कि क्या संस्था के आमंत्रण पत्र में पदाधिकारियों के नामों का क्रम तय करने के लिए कोई निर्धारित नियम या परंपरा है? यदि ऐसी व्यवस्था है,तो क्या सूची उसी के अनुरूप तैयार की गई? और यदि कोई औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं है,तो क्या नामों का क्रम तय करते समय पदों की जिम्मेदारी,वरिष्ठता और संगठनात्मक मर्यादा को ध्यान में रखा गया? किसी भी संस्था के आमंत्रण पत्र में नामों का क्रम केवल छपाई या सजावट का मामला नहीं होता,यह संस्था की औपचारिक व्यवस्था और पदाधिकारियों की भूमिका को भी दर्शाता है, इसलिए सूची तैयार करते समय स्पष्ट और सर्वमान्य आधार होना जरूरी है।

पदों की गरिमा और

संगठनात्मक मर्यादा का सवाल...

रेडक्रॉस सोसायटी जैसी सेवा संस्था से समाज सहयोग, संवेदनशीलता और पारदर्शिता की अपेक्षा करता है,संस्था के भीतर भी पदाधिकारियों के बीच समन्वय और परस्पर सम्मान का वातावरण होना चाहिए,किसी भी पद का महत्व उसकी जिम्मेदारी और संस्था के नियमों से तय होता है,यदि सूची के क्रम को लेकर कोई स्थापित प्रोटोकॉल है,तो उसका पालन होना चाहिए,यदि नहीं तो तैयार करते समय कोई त्रुटि हुई है,तो उसे स्पष्ट किया जा सकता है,और यदि क्रम किसी विशेष कारण से निर्धारित किया गया है,तो उस कारण की जानकारी सार्वजनिक करने से अनावश्यक भ्रम दूर हो सकता है,यह मुद्दा किसी एक पदाधिकारी को दूसरे से बड़ा या छोटा साबित करने का नहीं,बल्कि संस्थागत व्यवस्था की स्पष्टता का है,जनसेवा के मंच पर सभी पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी का सम्मान होना चाहिए।

आयोजकों से अपेक्षा-सेवा के साथ व्यवस्था पर भी स्पष्टता

रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है,इसलिए एंबुलेंस के संचालन से लेकर आमंत्रण पत्र की व्यवस्था तक,सभी पहलुओं में स्पष्टता कार्यक्रम की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी,आयोजन समिति यह बता सकती है कि नामों का क्रम किस आधार पर निर्धारित किया गया और क्या इसके लिए संस्था का कोई निर्धारित प्रोटोकॉल है, यदि यह अनजाने में हुई त्रुटि है,तो भविष्य में सुधार की गुंजाइश है। यदि क्रम निर्धारित नियमों के अनुसार है,तो उसका स्पष्टीकरण भी सामने आना चाहिए, इसी तरह एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता,संपर्क व्यवस्था और संचालन की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए,ताकि यह पहल केवल एक समारोह तक सीमित न रहकर जरूरतमंद मरीजों के लिए उपयोगी सेवा बन सके।

सेवा संकल्प की असली

कसौटी जमीन पर दिखने वाला काम

13 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘डॉक्टर आपके द्वार’ एंबुलेंस का शुभारंभ सूरजपुर जिले के लिए एक उपयोगी पहल साबित हो सकता है,रक्तदान शिविर, पौधरोपण,अंगवीर एवं रक्तवीर सम्मान और दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण जैसे कार्यक्रम भी समाजसेवा की भावना को आगे बढ़ाते हैं,लेकिन सेवा संकल्प की असली कसौटी कार्यक्रम की भव्यता नहीं,बल्कि उससे लोगों को मिलने वाला लाभ है,एंबुलेंस जरूरतमंदों तक पहुंचे,रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़े, दिव्यांगजनों को उपयोगी सहायता मिले और संस्था की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे-यही इस आयोजन की सार्थकता होगी,जनसेवा की पहल सफल है, लेकिन सेवा के साथ सम्मान,स्पष्ट व्यवस्था और जवाबदेही भी जरूरी है, एंबुलेंस के शुभारंभ के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि मरीजों को इसका लाभ किस तरह मिलता है और आमंत्रण पत्र में नामों के क्रम को लेकर उठे सवालों पर आयोजकों की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है।

छोटे कारोबारियों को स्वनिधि योजना का सहारा,वार्ड में शिविर लगाकर भरवाए आवेदन

पार्षद दीपक यादव की पहल,पात्र स्ट्रीट वैंडर्स को 15 हजार से 50 हजार तक ऋण दिलाने की प्रक्रिया में मदद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छोटे कारोबारियों और फुटपाथ पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को आर्थिक मदद दिलाने के उद्देश्य से शहीद भगत सिंह वार्ड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विशेष शिविर लगाया गया। वार्ड पार्षद दीपक यादव की पहल पर आयोजित शिविर में लोगों को योजना की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरवाए गए। योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को अपना काम शुरू करने, कारोबार बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए ऋण सहायता



उपलब्ध कराना है। शिविर के जरिए जरूरतमंदों को आवेदन प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया,ताकि जानकारी की अभाव या आवेदन संबंधी परेशानियों के कारण कोई पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। पार्षद दीपक यादव ने कहा कि छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार

से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित की जा रही है।

वार्ड में शिविर लगाने का उद्देश्य पात्र लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और आवेदन प्रक्रिया में उनकी मदद करना है। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि वार्ड का



प्रत्येक पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए।

योजना का लाभ लेने से पहले इन बातों पर ध्यान : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजना की पात्रता

और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले स्ट्रीट वैंडर्स आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आवेदन भरना ऋण स्वीकृति की गारंटी नहीं है। अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक और योजना के नियमों के अनुसार होगी।

वार्डवासियों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता संबंधी जानकारी की पुष्टि कर लें। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग वार्ड पार्षद कार्यालय या संबंधित निकाय से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पार्षद दीपक यादव ने कहा कि वार्ड में छोटे कारोबारियों को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे।

मुंह में था ट्यूमर 250 किमी दूर ले जाकर अजगर का ऑपरेशन

अंबिकापुर से बिलासपुर तक पहुंचाया गया इंडियन रॉक पाइथन,तीन घंटे की जटिल सर्जरी कर निकाला गया ट्यूमर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

एक बेजुबान वन्यजीव की जिंदगी बचाने के लिए सरगुजा से बिलासपुर तक 250 किलोमीटर का सफर तय किया गया। अम्बिकापुर में रेस्क्यू किए गए इंडियन रॉक पाइथन (भारतीय अजगर) के मुंह में ट्यूमर होने के कारण उसे बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर ले जाया गया। यहां वन्यजीवों के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. पिंप्पू दुबे ने करीब तीन घंटे तक चली जटिल सर्जरी कर ट्यूमर निकालने की प्रक्रिया पूरी की। फिलहाल ऑपरेशन के बाद अजगर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सत्यम द्विवेदी, जिन्हें स्नेक मैन ऑफ सरगुजा के नाम से जाना जाता है,ने अजगर के उपचार के लिए विशेष पहल की। समय पर उचित उपचार मिल सके,इसके लिए उसे अम्बिकापुर से बिलासपुर पहुंचाया गया। वन्यजीव के मुंह में ट्यूमर होने के कारण उसका उपचार चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सक की मदद से सर्जरी की गई।



स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे : सर्जरी के बाद अजगर की सेहत में सुधार और उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की योजना है। यह प्रयास वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी



की मिसाल है। अक्सर घायल या बीमार वन्यजीवों के उपचार में समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में एक बेजुबान जीव के उपचार के लिए लंबी दूरी तय करना और उसकी सर्जरी की व्यवस्था करना वन्यजीवों के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाता है।

पापर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर और अम्बिकापुर के माँ दुर्गा मंदिरों में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के लखनपुर एवं अम्बिकापुर स्थित माँ दुर्गा मंदिरों में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने पवित्र ज्योति के दर्शन किए तथा प्रदेशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की मंगलकामना की। इस अवसर पर मंत्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति, विकास और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की। मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंदिरों में श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा की आराधना की और प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा एवं खुशहाली बनी रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि माँ जगदंबा की असीम कृपा और आशीर्वाद से छत्तीसगढ़



निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो तथा प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करे,यही उनकी हार्दिक अभिलाषा है। इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि माँ दुर्गा शक्ति,साहस, करुणा और कल्याण की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी आराधना हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा,आत्मविश्वास और लोककल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारी सनातन संस्कृति में देवी आराधना का विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।



जंगल में आरा व कुल्हाड़ी चलता रहा, निगरानी का पहरा कहां था? अमहर बीट के कटे पेड़ पूछ रहे सवाल

सोनहत के अमहर बीट में जंगल पर आरा व कुल्हाड़ी! बेशकीमती साल की लकड़ियों की कथित तस्करी से हड़कंप

जंगल कटता रहा, वन अमला कहां रहा? अमहर बीट में साल के पेड़ों की कटाई से मचा हड़कंप

साल के जंगलों पर संकट! अमहर बीट में कटाई के निशान, वन संपदा की सुरक्षा पर सवाल

अमहर बीट में जंगल की बर्बादी के निशान, कथित लकड़ी तस्करी की आशंका से वन विभाग कठघरे में

कटे पेड़ों के तने, बिखरे छिलके और जंगल में लकड़ियों के अवशेष ने खोली निगरानी व्यवस्था की पोल? वन विभाग की जवाबदेही पर उठे सवाल...

—राजन पाण्डेय—

सोनहत/ कोरिया, 12 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जंगलों की सुरक्षा के लिए तैनात वन अमला आखिर कर क्या रहा है? क्या मैदानी निगरानी केवल सरकारी कागजों और गश्त के रजिस्टर तक सीमित रह गई है? क्या जंगलों के भीतर होने वाली गतिविधियों की जानकारी जिम्मेदार कर्मचारियों तक समय पर पहुंच रही है? कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र अंतर्गत अमहर बीट से सामने आए कटाई के निशानों ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जंगल के भीतर कटे पेड़ों के तने, लकड़ियों की छिलाई के बाद जमीन पर बिखरे अवशेष और कटाई के निशान वन संपदा की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने की जरूरत को रेखांकित कर रहे हैं।

स्थानीय स्तर से प्राप्त जानकारी और सामने आई तस्वीरों के आधार पर अमहर बीट में बेशकीमती साल के पेड़ों की कथित अवैध कटाई और लकड़ियों की तस्करी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि, कटाई की वास्तविक मात्रा, पेड़ों की प्रजाति, घटना का समय और लकड़ियों के परिवहन की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है, इसके बावजूद सवाल यह है कि यदि जंगल के भीतर पेड़ों की कटाई हुई है, तो इसका पता लगाने और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने के लिए वन विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? वन संपदा की सुरक्षा केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है, ऐसे में अमहर बीट का मामला केवल कटे पेड़ों की गिनती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नुकसान का आकलन होना चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निगरानी व्यवस्था ने कथित गतिविधियों को समय रहते क्यों नहीं रोका।

जंगल के भीतर कटे तने और बिखरे छिलके, आखिर क्या है पूरा मामला?

अमहर बीट से सामने आए दृश्य जंगल के भीतर हुई संभावित कटाई की जांच की मांग करते हैं, पेड़ों के कटे तने और लकड़ियों के अवशेष यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण भौतिक संकेत हो सकते हैं कि घटनास्थल पर किस प्रकार की गतिविधि हुई, लेकिन इन संकेतों के आधार पर ही कटाई की पूरी अवधि, लकड़ी की मात्रा या तस्करी में शामिल लोगों के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए

अमहर बीट में कटे पेड़, बिखरी लकड़ियां... अब सवाल— वन विभाग की गश्त आखिर किस काम की?

साल के जंगलों को नुकसान, पर्यावरण पर भी पड़ सकता है असर

साल के वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जंगलों में अनियंत्रित कटाई से प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं, इसका असर जैव विविधता, मिट्टी के संरक्षण और वन क्षेत्र पर निर्भर समुदायों पर भी पड़ सकता है, यदि अमहर बीट में साल के पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि होती है, तो नुकसान का आकलन केवल लकड़ियों की आर्थिक कीमत के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, यह भी देखा जाना चाहिए कि कितने पेड़ प्रभावित हुए, वन क्षेत्र को कितना नुकसान पहुंचा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से कदम आवश्यक हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हितों से भी जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाना और वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

वन विभाग को मौके पर पहुंचकर प्रत्येक कटे पेड़ के तूट का निरीक्षण करना होगा, पेड़ों की प्रजाति, तने की स्थिति, कटाई के निशान, लकड़ी के अवशेष और आसपास मौजूद संभावित रास्तों का दस्तावेजी आकलन आवश्यक है, यदि लकड़ियों को मौके पर ही छोटे हिस्सों में काटने या छल हटाने के संकेत मिलते हैं, तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए, सबसे अहम प्रश्न यह है कि क्या यह घटना किसी एक स्थान तक सीमित है या जंगल के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के निशान मौजूद हैं? क्या कटे पेड़ों की संख्या और लकड़ी की मात्रा का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान किया गया है? क्या किसी प्रकार की जल्दी या निरीक्षण की कार्रवाई हुई है? इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक गंभीरता का आकलन किया जा सकेगा।

कटाई से लेकर संभावित दुलाई तक, जांच के कई बिंदु?

अवैध लकड़ी कटाई के किसी भी मामले में केवल पेड़ काटने जाने की पुष्टि पर्याप्त नहीं होती, यह भी पता लगाना जरूरी होता है कि कटाई कब हुई, लकड़ी को मौके पर ही तैयार किया गया या नहीं, उसे कहाँ ले जाने की योजना थी और क्या उसका परिवहन किया गया, अमहर बीट में लकड़ियों के अवशेष और कटाई के निशानों को देखते हुए इन सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है, वन विभाग को घटनास्थल तक पहुंचने वाले रास्तों, आसपास की आवाजाही और संभावित परिवहन मार्गों की जानकारी जुटानी चाहिए, यदि किसी वाहन के इस्तेमाल का संदेह है, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसकी पड़ताल की जानी चाहिए, जांच में यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या जंगल से लकड़ी बाहर ले जाने के कोई निशान हैं और क्या संबंधित क्षेत्र में पहले भी ऐसी शिकायतें सामने आई थीं, यदि अन्य स्थानों पर भी समान प्रकृति के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके बीच संबंध की जांच की जा सकती है, हालांकि, अभी किसी संगठित तस्करी गिरोह या पूरे नेटवर्क की मौजूदगी को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, लेकिन संभावित अवैध कटाई और

सोनहत के जंगल में लकड़ी का खेल? कटे साल के तने और छिलकों ने खड़े किए गंभीर सवाल

हरे-भरे जंगल पर किसने चलाया आरा? अमहर बीट में कथित अवैध कटाई, निगरानी से लेकर जवाबदेही तक सवाल

उच्चस्तरीय जांच की जरूरत, केवल निरीक्षण नहीं जवाबदेही भी हो तय

अमहर बीट में सामने आए कटाई के निशानों और साल की लकड़ियों की कथित तस्करी की आशंका को देखते हुए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले का सज्ञान लेकर स्थल निरीक्षण कराना चाहिए, जांच में निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए...

- **कटे पेड़ों का आकलन:** पेड़ों की संख्या, प्रजाति, तूटों की स्थिति और लकड़ी की संभावित मात्रा का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया जाए।
- **घटना के समय का पता:** उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर यह जानने का प्रयास किया जाए कि कटाई कब हुई।
- **लकड़ी के परिवहन की जांच:** संभावित रास्तों, आवाजाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लकड़ी को जंगल से बाहर ले जाने की आशंका की पड़ताल की जाए।
- **गश्त रजिस्टर का मिलान:** संबंधित बीट में गश्त, निरीक्षण, शिकायत और कार्रवाई के अभिलेखों की समीक्षा की जाए।

- **अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका:** संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सुनते हुए यह जांचा जाए कि निगरानी में कोई चूक या नियमों की अनदेखी हुई या नहीं।
- **कानूनी कार्रवाई:** अवैध कटाई या तस्करी की पुष्टि होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।
- **भविष्य की रोकथाम:** संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और गश्त को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, इन बिंदुओं पर जांच होने से केवल वर्तमान घटना की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए भी ठोस आधार तैयार हो सकेगा।

लकड़ी के परिवहन की आशंका को गंभीरता से लेकर साक्ष्य जुटाना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

क्या अवैध लकड़ी कारोबार के पीछे संगठित गतिविधि है?

बेशकीमती लकड़ी की कथित कटाई और संभावित तस्करी की आशंका के बीच यह पता लगाना भी जरूरी है कि घटना में एक व्यक्ति की भूमिका है या कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्या पेड़ काटने, लकड़ी तैयार करने और उसे बाहर ले जाने की प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग लोगों की भूमिका रही? क्या लकड़ी का कोई संभावित खरीदार या गंतव्य था? क्या इससे पहले भी इसी क्षेत्र से लकड़ी बाहर ले जाने की शिकायतें मिली थीं? ये सभी जांच के विषय हैं, लेकिन इनके उत्तर बिना साक्ष्य के नहीं दिए जा सकते, किसी व्यक्ति, कारोबार या विभागीय कर्मचारी पर संरक्षण देने अथवा तस्करी में शामिल होने का आरोप तभी लगाया जाना चाहिए, जब उसके समर्थन में विश्वसनीय तथ्य उपलब्ध हों, वन विभाग को घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों, लकड़ी की संभावित मात्रा, परिवहन से जुड़े संकेतों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर मामले की जांच करनी चाहिए, यदि जांच में किसी संगठित गतिविधि या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, जंगलों की सुरक्षा किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती, यदि अवैध कटाई की पुष्टि होती है, तो कार्रवाई का आधार व्यक्ति की हैसियत नहीं, बल्कि

अब वन विभाग के जवाब का इंतजार

सोनहत वन परिक्षेत्र के अमहर बीट से सामने आए कटाई के निशानों ने वन संपदा की सुरक्षा और मैदानी निगरानी की प्रभावशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, अब जरूरी है कि वन विभाग सामने आए तथ्यों का भौतिक सत्यापन करे, नुकसान का आकलन करे और जांच के निष्कर्षों को स्पष्ट करे, क्या विभाग ने अमहर बीट का निरीक्षण किया है? क्या कटे पेड़ों

उपलब्ध साक्ष्य और लागू कानून होने चाहिए।
निर्माण कार्यों और विभागीय गतिविधियों के बीच वन संरक्षण की प्राथमिकता जरूरी
वन विभाग की जिम्मेदारी केवल कार्यालयीन कार्यों, निर्माण योजनाओं और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, जंगलों की सुरक्षा, अवैध कटाई पर रोक, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान से बचना भी विभाग के मूल दायित्वों में शामिल है, अमहर बीट से सामने आए दृश्य यह सवाल उठाते हैं कि मैदानी स्तर पर वन संरक्षण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, यदि जंगल के भीतर पेड़ों की कटाई होती है, तो उसका पता लगाने के लिए नियमित निगरानी कितनी महत्वपूर्ण है, यह स्पष्ट है, ऐसे में विभाग को अपनी गश्त व्यवस्था, कर्मचारियों की उपलब्धता और सूचना मिलने पर कार्रवाई की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए, यदि किसी क्षेत्र में निगरानी कमजोर है, तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, यदि कर्मचारियों की कमी है, तो उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखी जानी चाहिए, और यदि निगरानी उपलब्ध होने के बावजूद कथित अवैध गतिविधियां हुई हैं, तो यह पता लगाना जरूरी है कि चूक कहाँ हुई, वन संरक्षण की सफलता केवल योजनाओं और बजट के आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती, जंगलों की वास्तविक स्थिति, अवैध कटाई पर नियंत्रण और शिकायतों पर कार्रवाई भी इसकी महत्वपूर्ण कसौटियां हैं।

बीट गार्ड की निगरानी पर सवाल, गश्तका रिकॉर्ड क्या कहता है?

वन क्षेत्र की सुरक्षा में बीट स्तर पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, नियमित गश्त, जंगल की स्थिति पर नजर रखना, अवैध कटाई की आशंका वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करना और सख्त गतिविधियों की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना मैदानी निगरानी के आवश्यक हिस्से हैं, ऐसे में अमहर बीट में कटाई के निशान मिलने के बाद संबंधित बीट गार्ड की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है, सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित क्षेत्र में नियमित गश्त कब-कब हुई और उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या हाल के दिनों में जंगल का निरीक्षण किया गया था? क्या कटे पेड़ों या लकड़ियों के अवशेष पहले भी देखे गए थे? क्या किसी ग्रामीण या स्थानीय व्यक्ति ने इसकी सूचना दी थी? यदि संबंधित कर्मचारियों को घटना की जानकारी पहले से थी, तो यह देखना होगा कि सूचना मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई, वहीं, यदि उन्हें जानकारी नहीं थी, तो यह जांचना जरूरी होगा कि मैदानी निगरानी में कोई कमी रही या नहीं, इन सवालों का जवाब केवल मौखिक स्पष्टीकरण से नहीं मिलेगा, गश्त रजिस्टर, निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायतों का रिकॉर्ड और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई सूचनाओं का मिलान करना होगा, इसके बाद ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि घटना का पता लगाने में किसी प्रकार की चूक हुई या नहीं, यह भी जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो और संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सुना जाए, यदि लापरवाही प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, यदि किसी कर्मचारी की सल्लसलता के प्रमाण मिलते हैं, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुरूप कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी तय?

अमहर बीट में कथित अवैध कटाई की आशंका के बीच जवाबदेही का प्रश्न केवल बीट गार्ड तक सीमित नहीं रह सकता, जांच में यह भी देखना होगा कि संबंधित वन परिक्षेत्र में निगरानी और निरीक्षण की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही थी तथा वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति की जानकारी थी या नहीं, क्या नियमित निरीक्षण किए जा रहे थे? क्या कर्मचारियों की तैनाती और गश्त की व्यवस्था पर्याप्त थी? क्या पूर्व में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि शिकायत मिली थी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? इन बिंदुओं की जांच से विभागीय व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है, हालांकि, केवल कटाई के निशान मिलने से किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, जिम्मेदारी का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों, विभागीय अभिलेखों और निष्पक्ष जांच के आधार पर ही किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच की प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, यदि वन संपदा को नुकसान पहुंचने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों की पहचान और जवाबदेही तय करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

चाहिए, यदि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ निगरानी व्यवस्था में हुई किसी भी प्रमाणित चूक की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जंगलों की सुरक्षा केवल कागजों पर दर्ज जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला परिणाम होनी चाहिए, अमहर बीट के मामले में अब वन विभाग की कार्रवाई ही बताएगी कि वन संपदा की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों का जवाब कितनी गंभीरता से दिया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में संस्थागत प्रसव औसत से तीन गुना अधिक

सूरजपुर, 12 अक्टूबर। जिले के कलेक्टर रैना जमील तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रशांत सिंह के निर्देश व मार्गदर्शन के नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं के पंजीयन पश्चात नियमित समीक्षा पश्चात विकासखण्ड प्रतापपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के उद्देश्य से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक के ग्रामीण व शहरी छेत्रों के साथ ही आस-पास के चार ब्लॉकों राजपुर, बलरामपुर, वाड़फनगर व ओड़गी के समीपवर्ती ग्रामीण छेत्रों से गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तापूर्ण संस्थागत प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुभवी चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ व साथ आए मितानिनों के साथ सहयोगी स्टाफद्वारा कराया जाता है। बताते चले

कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रति माह 30 संस्थागत प्रसव कराया जाता होता है जिसके हिसाब से अब तक 180 संस्थागत प्रसव होना चाहिए जो अपने लक्ष्य से अधिक प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक कुल 417 संस्थागत प्रसव कराए जा चुके हैं जो दोगुने से अधिक है जिन्हें प्रसव पश्चात जननी सुरक्षा योजना से चौदह सौ रुपए प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जा रहें हैं

साथ-साथ अतिरिक्त पौष्टिक आहार जननी शिशु सुरक्षा योजना से उपलब्ध कराया गया है और महतारी एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से निःशुल्क घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी प्रसूताओं का प्रसव पश्चात अस्थायी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने तथा बच्चों में अंतर रखने के उद्देश्य से काउंसिलिंग पश्चात अब तक 144 महिलाओं का प्रसिद्धि स्टाफनर्स द्वारा कॉपर टी भी निवेशन किया जाकर प्रोत्साहन

राशि वितरण किया जा रहा है जिससे ग्रामीण छेत्रों में संस्थागत प्रसव की ओर जागरूकता बढ़ी है और सम्भावित खतरे भी कम हुए हैं। इस छेत्र में स्वास्थ्य विभाग के मितानिन, सीएचओ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजरों एवं सिक्रेट चिकित्सक व आरएमए तथा अन्य सहयोगी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहता है। जिसके कारण ब्लॉक सीएचसी प्रतापपुर की उपलब्धि अपने औसत लक्ष्य से अधिक है।



CMYK

अंत से आरंभ तक,फिर सिनेमाघरों में दहाड़ने की तैयारी में जुटे सनी देओल, सूर्या से दमदार लुक जारी

अपकमिंग फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक से सनी देओल का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। जारी किए गए मोशन पोस्टर में सनी देओल बेहद दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के जारी होते ही अभिनेता के फैंस ने इस पर रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर फिर कब्जा जमाने की तैयारी में जुट गए हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म से उनका पहला लुक जारी कर दिया गया है। सोमवार को सनी देओल ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक अपनी अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसे देखने के बाद अभिनेता के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस मोशन पोस्टर में सनी देओल बेहद दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम सूर्या: अंत से आरंभ तक है, जो इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगा। मेकर्स ने मोशन पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सूर्या: अंत से आरंभ तक का मोशन पोस्टर रिलीज
सूर्या के मोशन पोस्टर में सनी देओल व्हाइट टी-शर्ट में गंभीर लुक में दिखाई दे रहे हैं। उनकी नजरें झुकी हैं, लेकिन चेहरे



पर इंटेस इमोशन देखने को मिल रहे हैं और सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पर राैब उनके लुक को और किलर बना रहा है। वीडियो में बताया गया है कि इस अपकमिंग क्राइम-थ्रिलर में सनी देओल का किरदार अतीत और वर्तमान में उलझा हुआ होगा। फिल्म को लेकर मेकर्स ने अन्य डिटेल तो साझा नहीं की है, लेकिन दर्शक सनी देओल के धांसू लुक को देखकर जरूर इंप्रेस हैं। यूजर्स ने पोस्टर देखते ही मान लिया है कि ये फिल्म काफी पावरफुल होने वाला है।

सूर्या का पोस्टर देख इंप्रेस हुए फैन
सूर्या से सनी देओल का लुक जारी होते ही

उनके फैंस और फॉलोअर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। एक ने कमेंट करते हुए लिखा- सनी बिल्कुल किसी इंटरनेशनल हीरो जैसे लग रहे हैं। एक ने लिखा- सनी पाजी, बेहद जबरदस्त लुक, हम आपकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तुस्सी ग्रेट हो पाजी, लव यू सर। एक और लिखता है - उम्मीद है ये बटवारा 1947 जैसी नहीं होगी। एक ने लिखा- इसमें सनी देओल बहुत अलग लग रहे हैं।

फिल्म के बारे में
सूर्या: अंत से आरंभ तक की बात करें तो फिल्म 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। मोशन पोस्टर जारी करते हुए

मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है-अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ, वह सच का पता लगाता है। फिल्म का निर्देशन एम. पद्मकुमार कर रहे हैं और कमल मुकुट इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रज्ञा जायसवाल और रवि फिशान जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का मोशन पोस्टर देखने के बाद फिल्म को लेकर दर्शक जबरदस्त उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं।

सनी देओल का वकफट
सनी देओल की बात करें तो उन्होंने गदर 2 से जबरदस्त कमबैक किया था और इस साल रिलीज हुई बॉर्डर 2 को भी दर्शकों से जबरदस्त रिसांन्स मिला। ओटीटी पर रिलीज हुई इक्का को भी दर्शकों ने पसंद किया, लेकिन अगस्त 2026 में रिलीज हुई बंटवारा 1947 को कुछ खास रिसांन्स नहीं मिल सका। सनी देओल अब रणबीर कपूर स्टार रामायण में नजर आएंगे, जिसमें वह हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार संतोषी ने हाल ही में सनी देओल के साथ एक और फिल्म का ऐलान किया है, जिसका नाम घातक घुस के मारेगा है। इस फिल्म में सनी देओल अपने मशहूर घातक किरदार को एक नए अंदाज निभाते नजर आएंगे।

नेहा स्वामी का जन्मदिन: अर्जुन बिजलानी का रोमांटिक अंदाज



मशहूर टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अपनी पत्नी नेहा स्वामी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। अर्जुन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ यादगार और अनदेखे पलों का एक वीडियो मोटाज शेयर किया। लाफ्टर शेफ के कंटेस्टेंट अर्जुन ने बताया कि नेहा ही वो इंसान हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में स्थिरता (स्टेबिलिटी) लाई है। अर्जुन ने यह भी माना कि नेहा उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पंगा हैं। उन्होंने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा,हैप्पी बर्थडे माय लव। तुम गुस्सा हो या न हो, तुमने मुझे ज़िंदगी में जो दिया है-स्टेबिलिटी-उसके लिए मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा।हर चीज के लिए शुक्रिया नेहा! मैं हमेशा तुम्हारा प्लस वन रहूंगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पंगा हो!! इसके अलावा,टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को जन्मदिन की प्यारी सी बधाई दी। पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस ने बर्थडे गर्ल के साथ कुछ मजेदार तस्वीरें शेयर कीं और लिखा,प्यारी नेहा,जन्मदिन मुबारक हो...मेरी बेस्ट फ्रेंड,मेरी बहन और मेरी हमेशा चीयरलीडर रहने वाली नेहा, तुम अपनी मौजूदगी से ज़िंदगी को और रोशन कर देती हो। मुझे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा खूबसूरत दिल, तुम्हारी इमानदारी और जिस तरह तुम मुझे अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करती हो,वो सब बहुत पसंद है। और हाँ, तुम बहुत खूबसूरत और सेक्सी हो! उन्होंने आगे लिखा, हमेशा ऐसी ही चुलबुली,खुशमिजाज और निडर बनी रहो। नाचती रहो, बड़े सपने देखती रहो, जोर-जोर से हंसती रहो और अपनी उस खूबसूरत मुस्कान से हर महफ़िल में जान डालती रहो। भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ,कामयाबी,कॉन्फिडेंस, बेपनाह प्यार और ज़रन मनाने के लिए बहुत सारे शानदार मौके दें। साथ में और भी एडवेंचर्स, मजेदार पल और यादें बनाने का इंतज़ार रहेगा! तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड कहकर बुलाना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी...

कीर्ति केलकर ने पति शरद पर लुटाया प्यार,बताया बड़े दिल वाला इंसान

इस साल 7 अक्टूबर को एक्टर शरद केलकर 50 साल के हो गए। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस कीर्ति केलकर ने सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए एक प्यार सा नोट लिखा और उन्हें सबसे बड़े दिल वाला इंसान बताया। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जन्मदिन के सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां शेयर करते हुए कीर्ति ने लिखा,यह पोस्ट थोड़ी देर से आ रही है क्योंकि हम आपके जन्मदिन का ज़रन मनाने में पूरी तरह डूबे हुए थे। उस इंसान को जन्मदिन की बधाई (देर से ही सही) जिसके पास मेरा पूरा दिल है। (रेड हार्ट इमोजी) केशु के पापा, मेरे बाबू, हमारी ताकत, हमारा सहारा और हमारी छोटी सी दुनिया की जान। उन्होंने आगे कहा, मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, उनमें सबसे बड़े दिल वाले इंसान,जो बहुत गहराई से प्यार करते हैं, दिल खोलकर देते हैं और अपने आस-पास के हर व्यक्ति को ख़ास महसूस कराते हैं। आपका दिल इतना खूबसूरत है कि मुझे हर दिन आपसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। आप सिर्फ़ उस इंसान से कहीं ज्यादा हैं जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप वो इंसान हैं जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, जिनके साथ मैंने अपने सबसे खुशी के पल बाटे हैं, ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव देखे हैं, खूब बहस की है और खूब हंसी-मजाक किया है...कीर्ति ने कहा कि तानाजी: द अनसंग वॉरियर एक्टर के साथ ज़िंदगी प्यार,हंसी,मस्ती, यादों और लाखों छोटे-छोटे पलों से भरी रही है। उन्होंने आगे कामना की कि शरद को ज़िंदगी में वही सारा प्यार,खुशी और अपनापन वापस मिले जो वह अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी में लाते हैं। हर पड़व,हर उतार-चढ़ाव,हर बीते हुए कल और आने वाले कल में,आपके साथ ज़िंदगी और भी रोमांचक हो जाती है। जन्मदिन की बधाई (देर से ही सही),मेरे प्यार। आप हमारा घर,हमारा दिल और हमारी सब कुछ हैं। हम हर दिन आपका ज़रन मनाते हैं उन्होंने पोस्ट खत्म करते हुए कहा। शरद और कीर्ति ने 3 जून 2005 को एक पारंपरिक समारोह में शादी की थी। इस कपल की एक बेटी है, जिसका नाम केशा केलकर है।



एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने नवरात्रि के पहले दिन माता की चौकी में हिस्सा लिया। उन्होंने इस भक्तिमय शाम की कुछ झलकियां भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें वह मां के संगीत और कहानियों में पूरी तरह डूबी हुई नजर आईं। तस्वीरों और वीडियो में तमन्ना आरती में हिस्सा लेती और भजनों का आनंद लेती दिख रही हैं। तमन्ना के शेयर किए गए एक क्लिप में एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी नजर आ रही हैं। माता की चौकी में तमन्ना के माता-पिता भी मौजूद थे। तमन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा,ऊंचे सुरों वाले भजनों, मां की कहानियों और पहाड़ों से होते हुए वैष्णो देवी की यात्रा के ज़रिए आपको भक्ति का अनुभव कराती हैं, न कि सिर्फ़ उसे सुनाती हैं। हर गाने, हर कहानी और हर धुन के साथ,आप लगभग उस चढ़ाई,पवित्र रास्तों के खुलने और तीर्थयात्रा के ज़रिए खुद के और करीब जाने का एहसास कर सकते हैं।अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगीत और प्रार्थना में डूबने से उन्हें आत्म-चिंतन करने का मौका मिला और मन को

तमन्ना भाटिया का नवरात्रि जशन: घर पर रखी माता की चौकी

शांति भी मिली। इस दोहेरपन में कुछ बहुत खूबसूरत है। संगीत ऊपर उठता है, ऊर्जा पूरे कमरे में फैलती है और माहौल भक्ति से भर जाता है - फिर भी, कहीं भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वह सारा शोर और हलचल आपको भीतर की ओर खींचती है,आपको आपके केंद्र, यानी खुद से वापस जोड़ती है। संगीत,प्रार्थना और समर्पण के पांच घंटे ऐसे बीते जैसे कोई एक ही, कभी न खत्म होने वाला पल हो। जय माता दी, पोस्ट में आगे लिखा था। इससे पहले,तमन्ना ने बताया था कि कैसे उन्हें अपनी फिल्म द व्चान के छठ गीत की शूटिंग के दौरान एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। मेरे मन में छठ पूजा के लिए हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। गाने की शूटिंग शुरू करने से पहले,मैंने इस रस्म के महत्व और बिहार व पटना में इसे कैसे मनाया जाता है,इस बारे में पढ़ा और समझा। सच कहूँ तो, इसकी शक्ति के बारे में जानकारी मैं हैरान रह गई थी। छठी मैया के साथ मैंने जो गहरा जुड़ाव महसूस किया,उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।



हिंदी में भी आएगी ‘जेलर 2’,मेकर्स ने किया साफ

रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ की हिंदी रिलीज को लेकर चल रही खबरों पर फिल्म की टीम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मेकर्स ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि फिल्म हिंदी में भी सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसकी निर्धारित तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बयान के अनुसार, ‘जेलर 2’ गुरुवार,15 अक्टूबर 2026 को तमिल समेत अन्य भाषाओं के साथ हिंदी में भी प्रदर्शित की जाएगी। इससे हिंदी संस्करण की रिलीज को लेकर उठ रहे सवालों पर टीम का पक्ष सामने आ गया है। फिल्म की टीम ने अपने बयान में उन खबरों का उल्लेख किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ‘जेलर 2’ हिंदी में रिलीज नहीं होगी। मेकर्स ने स्पष्ट किया कि हिंदी वर्जन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सिनेमाघरों में आएगा। रिलीज की तारीख बदले जाने की बात को भी टीम ने खारिज किया है। हिंदी में फिल्म देखने की योजना बना रहे दर्शकों के लिए बयान का मुख्य संदेश यही है कि निर्धारित रिलीज कार्यक्रम बरकरार है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, उत्तर भारत में फिल्म के वितरण की जिम्मेदारी पेन मरुधर एंटरटेनमेंट को सौंपी गई है। मेकर्स ने वितरण से संबंधित यह जानकारी भी अपने स्पष्टीकरण में शामिल की है। हालांकि, बयान में उत्तर भारत के अलग-अलग शहरों, सिनेमाघरों और स्क्रीन की संख्या का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए हिंदी रिलीज की पुष्टि को किसी निश्चित संख्या में स्क्रीन या प्रत्येक मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शन की घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता।

खेल-समाचार

इंडिया बनाम श्रीलंका वनडे मैच का वेन्यू नहीं होगा चेंज

बीसीसीआई सचिव ने कहा...मैच शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं

नई दिल्ली,12 अक्टूबर 2026। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने वेन्यू बदलने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाला पहला वनडे मैच दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिसंबर के महीने में श्रीलंका की टीम भारत दौर पर आएगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 13 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले वनडे मैच को लेकर खबर थी कि दिल्ली में होने वाले वनडे मैच को अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा लेकिन अब इस खबर को बीसीसीआई ने गलत करार दिया है। हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी।



देवजीत सैकिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा?

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि दिल्ली से वनडे मैच शिफ्ट होने की खबर बिल्कुल गलत है। बीसीसीआई ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। देवजीत सैकिया ने दिल्ली

वनडे को अहमदाबाद शिफ्ट करने की खबर को नकारते हुए कहा कि दिल्ली में होने वाले भारत-श्रीलंका वनडे मैच को अहमदाबाद शिफ्ट किए जाने की खबर सही नहीं है। बीसीसीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वो कार्यक्रम से जुड़े अपडेट के लिए बीसीसीआई की आधिकारिक प्रेस रिलीज का सहारा लें। बाइलेटल सीरीज के मैचों को एक नीति का पालन करते हुए शहरों को दिया जाता है।

क्यों आई थी मैच शिफ्ट करने की खबरें?

दिल्ली से भारत-श्रीलंका वनडे मैच के शिफ्ट होने की खबरें इसलिए आ रही थीं क्योंकि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेनोवेशन का काम होना था। इसके तहत स्टेडियम की पिच, आउटफील्ड और ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाना था। ऐसी चर्चा थी कि इस काम की वजह

से मैच को किसी दूसरी जगह पर बदला जा सकता है, लेकिन बीसीसीआई ने इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए साफ कर दिया है कि मैच दिल्ली में ही होगा।

श्रीलंका दौर का शेड्यूल

श्रीलंकाई टीम इस साल दिसंबर में भारत दौर पर आएगी, जहां 13 दिसंबर को दिल्ली में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद, 16 दिसंबर को बेंगलूरु और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में अगले दो मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के लिए ये वनडे मैच काफी महम हैं क्योंकि इनसे टीम 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों का सही कॉन्डिनेशन तैयार कर सकेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 22 दिसंबर को राजकोट में पहला टी20 मैच खेला जाएगा, जबकि अगले दो टी20 मुकाबले 24 दिसंबर को कटक और 27 दिसंबर को पुणे में होंगे।

ईसीबी ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान,30 खिलाड़ियों को मिली जगह



मुंबई इंडियंस में शामिल हुई अमेरिका की घातक तेज गेंदबाज

नई दिल्ली,12 अक्टूबर 2026। विमेंस प्रीमियर लीग 2027 के लिए मुंबई इंडियंस ने तारा नॉरिस को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस तेज गेंदबाज को सिर्फ 10 लाख रुपये में ट्रेड किया गया है। मुंबई इंडियंस ने डब्ल्यूपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले यूपी वॉरियर्स के साथ यह अहम ट्रेड किया है। नॉरिस को यूपी वॉरियर्स ने 2026 सीजन से पहले 10 लाख रुपये में साइन किया था। वह अब उसी कीमत पर मुंबई इंडियंस में शामिल हो गई हैं। यह पूरी तरह से कैश डील है और बदले में मुंबई ने यूपी को कोई खिलाड़ी नहीं दिया है।

ब्रिसबेन,12 अक्टूबर 2026।

ईसीबी ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कुल 39 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 30 खिलाड़ियों को मुख्य सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और 9 को डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की है। इसमें 32 साल के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की टीम के साथ दोबारा वापसी हुई है, जिन्हें आखिरी बार साल 2023 में यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस बार बोर्ड ने कुल 39 खिलाड़ियों को चुना है, जिसमें 30 खिलाड़ियों को मुख्य सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और 9 खिलाड़ियों को युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।

7 खिलाड़ियों को पहली बार मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

इस नई लिस्ट में टॉम बैटन, सैम कुक, जॉर्डन कांक्स,हेनरी क्रोकोम्ब, एमिलियो गे,मैथ्यू फिशर और डैन लॉरिस जैसे 7 खिलाड़ियों को पहली



बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा,सोनी बेकर, जॉर्डन कांक्स और हेनरी क्रोकोम्ब के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर दो साल का कर दिया गया है। इन सभी 11खिलाड़ियों का यह कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर 2028 तक चलेगा।

इंग्लैंड ने प्यूचर को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के मकसद से डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी बदलाव किए हैं। इस कैटेगरी में जेम्स कोल्स, मेसन क्रेन,

बेन मैकिनी,लियाम पैटरसन-व्हाइट, थॉमस रीव और मैथ्यू रैक्स को पहली बार शामिल किया गया है। खास बात यह है कि मेसन क्रेन की वापसी आठ साल से अधिक समय बाद सीनियर टीम में हुई है, जबकि 18 साल के थॉमस रीव इस लिस्ट में सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की कप्तानी करके टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। इनके अलावा, जोश हल, एडी जैक और मिच स्टैन्ली भी इस

सूची का हिस्सा हैं, जिससे इस कैटेगरी में कुल 9 खिलाड़ी हो गए हैं।

ईसीबी ने कोचिंग स्टाफ में भी किया है बदलाव

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम के कोचिंग स्टाफ में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। अब माइक याडी को मुख्य बैटिंग कोच और रिचर्ड डॉसन को स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ट्रीय कुली अपनी तेज गेंदबाजी कोच की भूमिका में बने रहेंगे। टेस्ट टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ रिचर्ड डॉसन, मार्कस ट्रेस्कोथिक, जेम्स फोस्टर और एरिक सिम्स काम करेंगे।

इसके अलावा व्हाइट-बॉल के कोच ब्रेंडन मैककुलम के स्टाफ में सारा टेलर, जीवन पटेल और टिम साउदी को शामिल किया गया है, जबकि पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन को मेंटोर की खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नया कोचिंग स्टाफ इंग्लैंड के आगामी दौरों की तैयारी संभालेगा,जिसमें टीम को टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका और सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है।

ईसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी

जो रूट,हेरी ब्रूक,रेहान अहमद,जोफा आर्चर,गस एटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बैटन,शोएब बशीर,जैकब बथेल, जोस बटलर,ब्राइडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कांक्स,हेनरी क्रोकोम्ब, सैम करन,लियाम डॉसन,बेन डकेट, एमिलियो गे,मैथ्यू फिशर,विल जैक्स,डैन लॉरिस, साकिब महमूद,जेमी ओवरटन,ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स,आदिल रशीद,ओली रॉबिन्सन,फिल सॉल्ट,जेमी रिम्थ,जोश टंग

2026-27 के लिए इंग्लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट:

जेम्स कोल्स,मेसन क्रेन,जोश हल,एडी जैक,बेन मैकिनी, लियाम पैटरसन-व्हाइट,थॉमस रैव,मैथ्यू रैक्स,मिच स्टैन्ली

नाम परिवर्तन सूचना
मैं सुरेंद्र खांडे आओ शिवनंदन चौधरी,उम्र 23 वर्ष, जाति- चामार,निवासी- ग्राम पोतका,पोस्ट जामडीह,थाना उदयपुर,तहसील लखनपुर,जिला सरगुजा (छठगं) उपरोक्त पते का निवासी हूं।
यह कि मेरा पुराना नाम सुनील (Sunil) है और मैं अपना नाम बदलकर नया नाम सुरेंद्र खांडे (Suresndra Khande) करवाना चाहता हूँ। मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है। मैं अपना नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता हूँ तो मैं उसके स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। यह शपथ पत्र अपने होशों हवास में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर किया है।
सपथकर्ता सुरेंद्र खांडे

छत्तीसगढ़ में आज से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ ने पीवी ऐप की व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण नहीं होने, पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और वर्षों से लंबित मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय इकाई के आह्वान पर जिला शाखा रायपुर के सभी पटवारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश तिवारी के मुताबिक, पीवी ऐप के माध्यम से फसल के भौतिक सत्यापन के दौरान कई व्यवहारिक और तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर पूर्व में शासन और विभाग को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस और व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला गया है। संघ ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई है। संघ का आरोप है कि पटवारी पहले से ही कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों का जिम्मा संभाल रहे हैं। इनमें डिजिटल फ़ॉर्म सर्वे, एग्रीस्टैक पंजीयन, किसान पंजीयन, बकेट क्लेम, जनगणना के प्रश्न चरण, लघु सिंचाई संगठना, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वे, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, स्वामित्व योजना और सेवा संकल्प शिविर सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इसके बावजूद पीवी ऐप के बहिष्कार को लेकर बलौदाबाजार जिले में संघ के पदाधिकारियों और अन्य पटवारियों के तबादले तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है।



बीजापुर में 35 लाख के 6 इनामी माओवादियों का सरेंडर

ओडिशा में सक्रिय 4 कैडर भी शामिल, पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ने का फैसला

बीजापुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कुल 35 लाख रुपए के इनामी 6 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में ओडिशा में सक्रिय 4 माओवादी कैडर और पश्चिम बस्तर डिवीजन के संगठन से अलग होकर फरार हुए 2 माओवादी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इनमें 4 पीपीसीएम रैंक के कैडर और 2 पार्टी मेंबर हैं। पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों के लगातार नक्सल विरोधी अभियानों और पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रमों से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई में डीआरजी बीजापुर, सीआरपीएफ की 170वीं बटालियन और बीजापुर पुलिस के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

8-8 लाख के इनामी 4 पीपीसीएम कैडर शामिल : पुलिस द्वारा जारी जानकारी



लंबे समय से संगठन में सक्रिय छी रानी सोढ़ी

पुलिस के मुताबिक, रानी सोढ़ी उर्फ संध्या वर्ष 2012 से माओवादी संगठन में सक्रिय थीं। उसने बाल संधम सदस्य के रूप में शुरुआत की और बाद में पीएलजीए सदस्य तथा पार्टी सदस्य के रूप में काम किया। वर्ष 2022 में उसे पीपीसीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह ओडिशा राज्य की कंपनी नंबर 08 में सक्रिय रही।

के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में रानी सोढ़ी उर्फ संध्या, पांडो पोड़ियम उर्फ सरिमता, सुक्कू कुड़ियम उर्फ संतोष और कोसा माड़वी

उर्फ सतीश पीपीसीएम रैंक के माओवादी हैं। इन चारों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं, देवे मड़कम उर्फ जनी पर

2 लाख रुपए और लालू ताती पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इस तरह छह आत्मसमर्पित माओवादियों पर कुल 35 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों पर ओर

पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत ऐसे लोगों को पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य जीवन में लौटने के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। बीजापुर पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और पुनर्वास संबंधी प्रयासों से माओवादी संगठन पर दबाव बढ़ा है। छह कैडरों का आत्मसमर्पण इसी क्रम में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

जशपुर में 2 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत

मात-पिता और बेटे की जून गई, फ़रारहांगव में दुकान ने तोड़ दम

जशपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पहली घटना बगीचा थाना क्षेत्र के मैनी मोड़ की है, जहां हाईवा की टक्कर से बाइक सवार दंपती और 16-17 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं, दूसरी घटना पथलगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-43 पर कछार के पास हुई, जहां 2 बाइकों की आमने-सामने भिड़त में 18 वर्षीय शिवनंदन नाग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस दोनों हादसों की जांच कर रही है। पहला हादसा बगीचा थाना क्षेत्र के मैनी मोड़ पर हुआ। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात बाइक पर सवार होकर नईर साय (45), पत्नी शांति (40) और उनका करीब 16-17 साल का बेटा ब्रिशनंद अंबिकापुर की ओर से मैनी जा रहे थे। इसी दौरान मैनी की ओर से अंबिकापुर जा रहे हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बाइक ब्रिशनंद चला रहा था। बाइक पर नंबर भी दर्ज नहीं था। तीनों बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबार गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शवों को शव वाहन से बगीचा अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद हाईवा-टेलर चालक के मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। दूसरा हादसा पथलगांव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-43 पर कछार के पास कृष्णा राइस मिल के सामने हुआ। रविवार रात 2 बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 18 साल के शिवनंदन नाग की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। शिवनंदन नाग काउंटों गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक, वह अपने भांजे के घर त्रिसोट गांव आया हुआ था। सोमवार रात वह अपने किसी चाचा से बाइक मांगकर एक युवक को साथ लेकर पल्सर से लुढ़ाई की ओर जा रहा था। इसी दौरान कछार के पास सामने से आ रही प्लेटिना बाइक से उसकी टक्कर हो गई।



प्रदेश के 31,022 किसानों को मिलेगा 51.09 करोड़ रुपये का बोनस...

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 रुपये प्रति किंवटल से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति किंवटल किए जाने से गन्ना किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से लिए गए इस निर्णय से गन्ना किसानों को बढ़ी हुई दर से बोनस का लाभ मिलेगा। इस निर्णय के फलस्वरूप पेराई सत्र 2025-26 में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर, कवर्धा को गन्ना बेचने वाले 14,961 किसानों को लगभग 24.55 करोड़ रुपये की बोनस राशि प्राप्त होगी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए बोनस गणना में एफआरपी 329.05 रुपये प्रति किंवटल का आधार लिया गया है। बढ़ी हुई दर के अनुसार 425 रुपये में से एफआरपी घटाने पर किसानों को 95.95 रुपये प्रति किंवटल की दर से बोनस मिलेगा। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पेराई सत्र 2025-26 के दौरान कुल 25,58,188 किंवटल गन्ने की पेराई हुई।

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा: राजीव भवन में पहुंचाए गए 880 करोड़, पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल की 9.06 करोड़ की संपत्ति अटैच

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के रायपुर जोनल ऑफिस ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत 9 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट, रायपुर में एक सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंफ्लेंट दायर की है। ईडी ने 8 अक्टूबर को रायपुर में 9.06 करोड़ रुपये की कीमत वाली दो अचल संपत्तियों को जब्त करने का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी किया है। उन्हें इस मामले में 11 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच ईओडब्ल्यू/एसबीबी, रायपुर द्वारा अनिल टुटेजा, अनवर देबर, अरुण पति त्रिपाठी, कवासी लखमा और अन्य के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज



एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। जांच से पता चला कि 2019 से 2023 के दौरान एक शराब सिंडिकेट ने आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नियंत्रित किया और देशी शराब की सप्लाई (भाग ए), नकली होलोग्राम वाली सरकारी



दुकानों के माध्यम से बिना हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री (भाग बी), डिस्ट्रिलर्स से सालाना कमीशन (भाग सी) और विदेशी शराब के लिए एफएल-10ए लाइसेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध कमीशन से 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से प्राप्त आय अर्जित की।

राजीव भवन में पहुंचाया जाता था बड़ा हिस्सा

ईडी की जांच से पता चला है कि सिंडिकेट द्वारा अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल द्वारा संभाला जाता था और रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर रायपुर के शंकर नगर स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय, राजीव भवन में पहुंचाया जाता था। यह नगदी सिंडिकेट से जुड़े लोगों द्वारा ले जाई जाती थी और राजीव भवन में रामगोपाल अग्रवाल के अधीन काम करने वाले अकाउंटेंट देवेन्द्र दादसेना को सौंपी जाती थी।

9.06 करोड़ के दो प्लैट अटैच

जांच से पता चला है कि शराब घोटाले से जुड़ा लगभग 860 से 880 करोड़ रुपये का कैश इसी चैनल के जरिए पहुंचाया गया था। इसमें से लगभग 72 करोड़ रुपये रामगोपाल अग्रवाल के कंट्रोल में रहे और उनके कहने पर ही रखे गए, इस्तेमाल किए गए या बांटे गए। सिंडिकेट के उस समय के डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान इस कैश पहुंचाने के तरीके और उनकी भूमिका की पुष्टि करते हैं। रायपुर के अनुपम नगर और कटोरा तालाब में उनके दो प्लैट, जिनकी कीमत 9.06 करोड़ रुपये है, उन्हें उतनी ही कीमत की संपत्ति के तौर पर अस्थायी रूप से अटैच (जब्त) किया गया है। इससे पहले, इस मामले में ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में एक प्रॉसिक्यूशन कंफ्लेंट और छह स्प्लेमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंफ्लेंट दायर की थीं। साथ ही, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल टुटेजा, अनवर देबर, अरुण पति त्रिपाठी और चैतन्य बघेल समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था और 601.28 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच, जब्त या फ्रीज की थी।

सहायक शिक्षक भर्ती... हाईकोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापन में संशोधन

ब्लाइंड-डेफ और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता दी गई है। प्रश्न में सहायक शिक्षक के कुल 2292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद शामिल हैं। इसके लिए आवेदन की तारीख अलग से घोषित होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदले पात्रता संबंधी नियम : लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 (मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) में 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए निर्णय के पालन में संशोधन किया गया है। जारी शुद्धि पत्र के अनुसार, समाज कल्याण विभाग की



11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के अनुरूप सहायक शिक्षक पद के लिए उपयुक्त दिव्यांगता की श्रेणियों में ब्लाइंड, डेफ और सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विस्तृत विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड को विलोपित कर दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का समूहवार और श्रेणीवार विवरण भी निर्धारित निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के तहत कुल 2292 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद हैं।

सुकमा में नक्सल डम्प से 13 हथियार, 208 डेटोनेटर बरामद

आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना पर पालाचलमा जंगल में सर्चिंग, बीजीएल लॉन्चर और कारतूस भी मिले

सुकमा, 12 अक्टूबर 2026। सुकमा जिले के किरदाराम थाना क्षेत्र के पालाचलमा गांव के पहाड़ी-जंगल इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के छिपाए डम्प से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान 13 हथियार, 46 जिंदा कारतूस और 208 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत अन्य सामग्री मिली।

सूचना के आधार पर जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग

पुलिस के मुताबिक, नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जंगलों और दुर्गम



इलाकों में छिपाकर रखे गए हथियारों और विस्फोटक सामग्री की तलाश की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मयंक गुजर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने 12 अक्टूबर को

पालाचलमा के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखा गया डम्प मिला। टीम ने वहां मौजूद हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सामग्री को सुरक्षित कब्जे में लिया।

डिप्टी-कलेक्टर पर 3 करोड़ और लग्जरी कार मांगने का आरोप पत्नी बोली-प्रेग्नेंसी के दौरान मारपीट, पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर

रायपुर, 12 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला ने अपने पति डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। सद्दृक के मुताबिक, पति और ससुराल पक्ष पर लग्जरी कार के साथ 2 से 3 करोड़ रुपए दहेज में मांगने का आरोप है। पत्नी का कहना है कि, मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला महिला थाने इलाके का है।

शादी के दूसरे दिन से दहेज को लेकर ताने मारे : शिकायत के अनुसार, पूजा की शादी जुलाई 2024 में धर्मपते के जोधापुरा वार्ड निवासी मनोज बंजारे से हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने सोने के जेवर और घरेलू सामान दिया था। आरोप है कि, शादी के दूसरे दिन से ही कम दहेज लाने को लेकर ताने दिए जाने लगे। ससुराल पक्ष कथित तौर पर कहता था कि, डिप्टी



जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपए लाने का दबाव

पूजा ने आरोप लगाया कि, जनवरी 2025 में पति ने मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपए लाने का दबाव बनाया। रकम लाने में असमर्थता जताने पर मारपीट किए जाने की शिकायत भी की गई है। शिकायत में गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना और प्रसव के खर्च को लेकर विवाद का भी जिक्र है।

प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद नवजात के साथ मायके छोड़ा

पूजा के मुताबिक, मई 2025 में प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद उसे नवजात के साथ मायके छोड़ दिया गया। इसके बाद ससुराल पक्ष ने उससे संपर्क करना भी बंद कर दिया। पत्नी ने शिकायत में इस पूरे घटनाक्रम को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हिस्सा बताया है।

कलेक्टर होने के कारण मनोज की शादी किसी संपन्न परिवार में होती तो करोड़ों रुपए और लग्जरी कार मिलती।

मायके पहुंचकर गाली-गलौज और मारपीट की शिकायत

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, अप्रैल और सितंबर 2026 में पति अपने भाइयों के साथ मायके पहुंचा। इस दौरान गाली-गलौज, तोड़फोड़ और हमला किए जाने की बात कही गई है। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पूजा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकती है।

सुसाइड-नोट और परिजनों की गवाही से साबित हुई प्रताड़ना

हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा रखी बरकरार, आरोपी को 4 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

बिलासपुर, 12 अक्टूबर 2026। रायपुर के 36 सिटी मॉल स्थित सिनेमा हॉल में महिला के सुसाइड केस में हाईकोर्ट ने आरोपी को अपील खारिज कर दी है। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी बाबूली सिंह उर्फ बबलू उर्फ बोध सिंह की 5 साल की सश्रम कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी है। निचली अदालत ने उसे महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने आरोपी को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने और सजा भुगतने का आदेश दिया है। अगर वह तय समय में सरेंडर नहीं करता है, तो ट्रायल कोर्ट उसे हिरासत में लेकर सजा भुगतने की कार्रवाई करेगा। अभियोजन के मुताबिक,

24 मई 2013 को रायपुर के 36 सिटी मॉल स्थित सिनेमा हॉल में मंजू शर्मा ने सल्फास खा लिया था। उन्हें इलाज के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम



रिपोर्ट में जहर खाने से दिल और सांस लेने में दिक्कत होना मौत की वजह बताई गई। एफएमएसएल की जांच में भी उनके शरीर के अंगों के नमूने (विस्सरा) में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जहर की पुष्टि हुई। पुलिस ने मंजू शर्मा के पर्स से सुसाइड नोट, सल्फास की पुडिया, फोटो और पहचान पत्र जब्त किए थे। राज्य एफएमएसएल के हैंड रिटैन एक्सपर्ट ने दस्तावेजों पर लिखावट और हस्ताक्षरों की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि सभी दस्तावेजों पर लिखावट एक ही व्यक्ति की थी। मृतका की मां ने कोर्ट में बताया था कि घटना से दो-तीन महीने पहले उनकी बेटी ने आरोपी की प्रताड़ना और बेटे को अपावा करने की धमकी मिलने की बात बताई थी।